



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई, दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27, 1965/फाल्गुन 8, 1886

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27, 1965/PHALGUNA 8, 1886

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

बजट 1965-66

वित्त मंत्री का भाषण

27 फरवरी, 1965

महोदय

मैं भारत सरकार का 1965-66 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अवसर पर, जो स्वाधीन भारत का ऐसा पहला अवसर है जब हमारे प्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू इस कार्यवाही में मौजूद नहीं हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने उनका अभाव खटक रहा है और मुझे विश्वास है कि हम सबकी भावना भी यही है। इसलिए, माननीय सदस्यों की अनुमति से, उनकी पुण्य स्मृति में अपनी तुच्छ श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरान्त मैं अपना भाषण प्रारम्भ करूँगा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सत्रह वर्ष की लम्बी अवधि तक जवाहरलाल नेहरू, भारतीय मंच पर अपना प्रभाव डालते रहे और एक राष्ट्र के रूप में हमारी महत्वाकांक्षाओं को सार्थक और साकार बनाते रहे। हमारे जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं है—चाहे उसका सम्बन्ध देश की एकता से हो या उज्ज्वल भविष्य के लिए

आर्थिक आयोजना से अथवा राष्ट्रो के बीच शान्ति और सद्भाव बनाये रखने से—जिस पर उनकी असदिग्ध प्रतिभा की छाप न पड़ी हो। बजट और आर्थिक नीति जैसी दुनियावी बातों को भी ऐसे ऊँचे धरातल पर पहुँचा दिया गया जहाँ वे आर्थिक स्वतन्त्रता और सामाजिक न्याय से युक्त समृद्धि के समुज्ज्वल लक्ष्य की ओर प्रगति करने के साधन बन गये। अब हमारा, मेरे नेता प्रधान मंत्री, मन्त्रिमंडल के उनके सहयोगियों और निश्चय ही माननीय सदस्यों और देश के बाकी सभी लोगों का काम है कि हम सब अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू की परम्परा को आगे बढ़ावें। और मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि जो बजट मैं पेश करने जा रहा हूँ उससे कुछ सीमा तक इस दायित्व की पूर्ति हो सकेगी।

2. कई दृष्टियों से इस वर्ष के बजट का असाधारण महत्व है। चालू आयोजना-अवधि का अन्तिम बजट होने के कारण यह तीसरी आयोजना की पूर्ति में हमारे प्रयत्नों की पराकाष्ठा का प्रतीक है। साथ ही, यह पहले से अधिक जटिल और सांसारिकता से ओतप्रोत तथा वास्तव में कठिन उन कार्यों की भूमिका का भी द्योतक है, जो हमें चौथी आयोजना में पूरे करने हैं। माननीय सदस्य अब जान चुके हैं कि चौथी आयोजना के सम्बन्ध में हमारे प्रारम्भिक विचार क्या हैं। विकास सम्बन्धी हमारी आयोजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति करने के अलावा बजट सम्बन्धी नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो तात्कालिक समस्याएँ हर साल हमारे सामने उपस्थित होती हैं उन पर उसका असर पड़े। आर्थिक स्थिति की उन खास खास बातों के सम्बन्ध में, जिनके कारण हम पिछले साल चिन्ता में पड़ गये—जैसा कि बढ़ते हुए मूल्य, निवेश के लिए पर्याप्त साधन जुटाने की कठिनाइयाँ और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में तेजी से होने वाली कमी—मैंने इस सभा में समय-समय पर वक्तव्य किये हैं। पिछले वर्ष की भाँति, आर्थिक समीक्षा भी बजट से कुछ दिन पहले ही प्रकाशित कर दी गयी है और उस हद तक आज का मेरा काम कुछ हलका हो गया है। अतएव, चालू वर्ष के लिए बजट सम्बन्धी परिणाम का जो अनुमान अब किया गया है उसे मैं तत्काल ही बता रहा हूँ।

3 बजट में कुल 97 करोड़ रुपये की अपूर्ति कमी का अनुमान किया गया था। अब जान पड़ता है कि इस कमी में कुछ और घटती हो जायगी और कुल रकम लगभग 80 करोड़ रुपया रहेगी। कई दिशाओं, राजस्व और पूँजी दोनों में, खर्च में भारी वृद्धि होती हुई भी ऐसा सम्भव हो सका है। विस्थापितों की सहायता और पुनर्वास पर 12 करोड़ रुपया अधिक खर्च हुआ है। महगाई भत्ते की वृद्धियों के कारण इस साल खर्च में 38 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पूँजी खाने में, रामायनिक खादों की पहले की अपेक्षा अधिक खरीद और भारतीय खाद्य निगम के लिए और अधिक धन की व्यवस्था के अलावा, मुख्यतः अर्थोपाय सम्बन्धी अग्रिमों के कारण, राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों, और पंचवर्षीय आयोजना सम्बन्धी योजनाओं, खास कर कृषि, मिर्चाई और बिजली सम्बन्धी योजनाओं के लिए पहले से अधिक केन्द्रीय सहायता दिये जाने के कारण 85 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हुई है। किन्तु अन्य मदों के अन्तर्गत खर्च में कमी होने और राजस्व सग्रह में वृद्धि होने से ये अतिरिक्त परिणाम प्रतिसन्तुलित (बराबर) हो गये हैं। केन्द्रीय पूँजी परिव्यय में हुई कमी का सम्बन्ध मुख्यतः इस्पात के सयत्तों, रक्षा और खाद्य सामग्री की खरीद पर किये गये वास्तविक परिव्यय से है। खर्च में हुए परिवर्तनों का व्योरा, पहले की ही तरह, व्याख्यात्मक जापन में दे दिया गया है।

4. सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत राजस्व-सग्रह में 49 करोड़ रुपये की वृद्धि और आय तथा निगम करों के अन्तर्गत 66 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी प्राप्ति के उतनी ही रहने का अनुमान है जितनी बजट में दिखाई गयी थीं। राजस्व-व्यय में

42 करोड़ रुपये की कमी के साथ-साथ, जो कई शीर्षकों में बंटी हुई है, अब राजस्व अधिशेष 229 करोड़ रुपया, रहने का अनुमान है, जब कि बजट में 83 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था।

5. पूंजी प्राप्तियों के अन्तर्गत, इस वर्ष छोटी बचतों के अन्तर्गत उस्ताहवर्धक संग्रह हुआ है और अनुमान है कि उनकी रकम 135 करोड़ रुपये तक पहुँचेगी, जब कि बजट अनुमान 125 करोड़ रुपये का था। लेकिन बजट अनुमानों की तुलना में, सरकार के पास जमा रेलवे निधियों (रेलवे फण्ड्स) में कमी हुई है और विदेशी श्रृणों से होने वाली प्राप्तियों में भी 43 करोड़ रुपये की कमी होने की संभावना है।

6. माननीय सदस्य देखेंगे कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए—जिनका जिक्र मैंने अभी ही किया है, जैसे कि महंगाई भत्ते में वृद्धि, विस्थापितों का पुनर्वास और राज्यों को सहायता—अतिरिक्त और भारी आवश्यकताओं के होते हुए भी चालू वर्ष का सम्पूर्ण घाटा मूल अनुमान से कुछ कम रहेगा। अंशतः इससे हमारे उन प्रयत्नों की सफलता का पता चलता है जो हमने पिछला बजट पेश होने के बाद, खर्च में कमी करने के लिए किये थे। अन्य प्रकार से परिस्थिति कठिन होते हुए भी, सारे घाटे का कम हो जाना कुछ सन्तोष का विषय है। किन्तु अर्थ-व्यवस्था में मुद्राबाहुल्यकारी दबावों के होते हुए, अप्रत्यक्ष और परिहार्य व्यय पर नियंत्रण रखने और किये गये परिचयों से अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करने की अब भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले थी। केवल इसी मार्ग से हम शीघ्रतापूर्ण आर्थिक विकास और देश तथा विदेश सम्बन्धी वित्तीय स्थिरता की अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

7. माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी गया होगा कि इस वर्ष राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष के राजस्व-अधिशेष से भी अधिक रहेगा। किन्तु समूची अर्थव्यवस्था की स्वस्थता और स्थिरता के लिए जो बात वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है सम्पूर्ण स्थिति, जिसमें राजस्व और पूंजी खाते दोनों शामिल हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में, जिसमें आयोजना सम्बन्धी परिचय बराबर बढ़ते जा रहे हों, पूंजीगत बजट की केवल स्वेच्छापूर्ण बचतों के संग्रह और विदेशी सहायता से ही सन्तुलित नहीं रखा जा सकता। राजस्व सम्बन्धी अधिशेष द्वारा प्राप्त जनता की बचत की रकमों से इनकी अधिक से अधिक पूर्ति की जानी चाहिए। अतएव, इस वर्ष का भारी राजस्व अधिशेष उचित दिशा में ले जाने वाला प्रयत्न है।

8. जहां तक अर्थव्यवस्था में विकास का सम्बन्ध है, कृषिजन्य पदार्थों के उत्पादन में 1963-64 के मौसम में, उससे एक वर्ष पहले की कम उपज की अपेक्षा, थोड़ी वृद्धि हुई थी। चालू वर्ष में इस बात की बहुत सम्भावना है कि अनाज और व्यापारिक फसलों की कुल उपज में वृद्धि होगी और वह भी काफी। यदि परिस्थितियाँ सामान्य होतीं, तो कृषि पदार्थों की उपज बढ़ने से, मूल्यों में जो बहुत अधिक चढ़ाव आया है वह घट जाता। किन्तु अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न-स्तरों पर मुद्रा बाहुल्यकारी दबाव पड़ने और माल को सट्टे की भावना से दबा कर रखे जाने से मूल्यों में उतनी गिरावट नहीं आयी जितनी आनी चाहिए थी राजस्व और मुद्रा-विषयक जो उपाय हमने किये हैं और अब जो कर रहे हैं उन से मुझे आशा है, मूल्यों में उतनी सीमा तक गिरावट आ जायगी जितनी आर्थिक दृष्टि से उचित है। फिर भी हम इस बात की सावधानी रखेंगे कि अनाज की खरीद के लिए हमने जो अभिकरण स्थापित किये हैं वे मूल्यों के उन स्तरों पर बनाये रखेंगे, जो किसान के लिये लाभदायक होंगे, जिससे उसे और अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इस के साथ

ही, ये अभिकरण सम्भरण (सप्लाई) के सुधार से लाभ उठा कर सकट की स्थिति से बचने के लिए अनाज के भंडार तैयार रखेंगे, ताकि भविष्य में कृषिजन्य पदार्थों की उपज में किसी तरह की घटबढ़ होने पर वे स्थिति का पहले की बनिस्बत ज्यादा अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें।

9 पिछले दो वर्षों से औद्योगिक उत्पादन में 8से 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। चालू वर्ष की पहली छमाही में उत्पादन की गति में घीमेपन के कुछ लक्षण दिखायी दिये थे। किन्तु चालू राजस्व वर्ष की दूसरी छमाही में औद्योगिक उत्पादन के पूर्वस्थिति में आ जाने की आशा है और इस तरह पूरे वर्ष के उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। कृषि-पदार्थों की उत्पादन-वृद्धि को मिलाकर, 1963-64 की अपेक्षा—जब राष्ट्रीय आय में वास्तविक रूप में अनुमानित लगभग 4½ प्रतिशत की वृद्धि हुई—1964-65 में अर्थ-व्यवस्था के विकास का अनुपात अधिक होना चाहिए।

10 अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में, जैसे इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, सूत-कताई आदि में, उत्पादन में और अधिक वृद्धि नयी क्षमता की स्थापना पर निर्भर होगी। सरकारी क्षेत्र में इस्पात, मशीनों के निर्माण, रासायनिक खाद के उत्पादन आदि के विस्तार-कार्यक्रम प्रगति कर रहे हैं और इन से आगे के दो-तीन सालों में उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। भारतीय उद्योग अब ऐसी मजिल पर पहुँच गया है जहाँ से वह विकास की नयी तथा समिश्र दिशाओं में फैल सकता है और उसे फैलाना चाहिए भी। क्षमता के जिस विस्तार की आवश्यकता हमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में है वह न सिर्फ जमे हुए उद्योगों में होनी चाहिए, बल्कि उस से भी अधिक नए-नए उद्योगों में, जहाँ पूँजी और तकनीकी अनुभव की बड़ी आवश्यकता है। निवेश (इन्वेस्टमेंट) के लिए लाभ की रकमों का और अधिक उपयोग करने को प्रोत्साहन देने और गैर सरकारी उद्योग को पहले की अपेक्षा अधिक ऋण देने के लिए हमने बहुत से उपाय किये हैं। इसी तरह पहले से अधिक व्यक्तिगत बचतों के निवेश को प्रोत्साहन देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्तिगत नागरिक औद्योगिक विकास में ज्यादा-से-ज्यादा हाथ बटा सके। जो नयी वित्तीय संस्थाएँ हम ने स्थापित की हैं, वे जानकारी फैलाकर और दूसरे उपायों से ताकि लोग इस बात का ज्यादा अच्छा निर्णय कर सकें। कि उन्हें किस तरह के उद्योग में अपना पैसा लगाना चाहिए—इस काम में सहायता पहुँचा सकती है। लेकिन इस दिशा में सबसे पहला उद्देश्य व्यक्तिगत बचतों की शक्ति को बढ़ावा देना और उद्योग के काम में सुधार करना होना चाहिए, ताकि उद्योग कमाई कर सके और लगायी गयी पूँजी के लिए आकर्षक लाभ दे सके।

11. उद्यम चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी उनके मंचालन में कुशलता बहुत कुछ समुचित मूल्य-निर्धारण नीतियों पर निर्भर है। एक तरफ उद्योगों द्वारा दुर्लभ साधनों और सामग्रियों के लिए दिये जाने वाले मूल्यों से उनकी वास्तविक दुर्लभता प्रकट होनी चाहिए। जिनका वे इस्तेमाल करते हैं, साथ ही उद्यमों द्वारा बनायी गयी वस्तु के लिए जो मूल्य लिए जायें उन से, उपभोक्ता का शोषण किये बगैर, उद्योग को अपने विस्तार के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिए। इन्हीं सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर हम कृषिजन्य वस्तुओं के लिए एक मूल्य-ढाँचा तैयार करने की चेष्टा कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादनों के सम्बन्ध में भी, बनायी गयी वस्तुओं के मूल्यों में आवश्यकतानुसार वृद्धि की अनुमति देते हुए, अर्थ-व्यवस्था में बचतों और विदेशी मद्रा की दुर्भलता को ध्यान में रखते हुए हम ने पूँजी और आयातों के मूल्यों में वृद्धि करने का यत्न किया है। कच्चे माल को लगातार तंगी और मूल्यों के चढ़ाव के बाव-जूद, मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने की नीति को, जिसे 1963 में आरम्भ किया गया था, पिछले बजट के बाव से आगे बढ़ाया गया है, खासकर इस्पात की वस्तुओं के सम्बन्ध में। हमने कई बनियादी चीजों, जैसे कोयले, के मूल्यों में भी समय-समय पर आवश्यक सीमा तक वृद्धि की है।

12 उत्पादन-क्षमता की वृद्धि और मूल्य-निर्धारण की उपयुक्त नीति सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी गैर-सरकारी उद्योगों के लिए। मैंने अपने पिछले

बजट भाषण में इस बात के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि प्रायोजनाओं का चुनाव, लागत और लाभ का पूरा विचार करने के बाद, बहुत सावधानी से किया जाना चाहिये। प्रायोजनाओं का सतर्कनापूर्ण चुनाव, शीघ्रतापूर्ण क्रियान्विति, कुशलतापूर्ण कार्य-संचालन, मूल्य-निर्धारण की उपयुक्त नीतियाँ और लगायी गयी पूँजी पर समुचित लाभ ये सभी शीघ्रतापूर्ण विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। इसी भाव से, हमें गहराई में जाकर आयोजनाएं बनाने की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। पहले से लगायी गयी पूँजी से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना भाग्य की प्रगति का सर्वोत्तम मार्ग है। स्थिति को सुदृढ़ बनाना और विस्तार करना, भूमि पर दृढ़ता से कदम डालना और नजर ऊँची रखना ये परस्पर-विरोधी नहीं, बल्कि पूरक लक्ष्य हैं।

13 यह कुछ सन्तोष का विषय है कि मुद्रा और ऋण के क्षेत्र में मुद्रा-वृद्धि की गति, जो 1963-64 में बहुत तेज थी, चालू वर्ष में कुछ कम हो गयी है। बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋण में इस वर्ष कुछ कम वृद्धि हुई है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से, सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार-ऋणों का कुछ अंश रिजर्व बैंक को खरीदना पड़ रहा है। इस सीमा तक, लम्बी अवधि के लिए, लिये गये हमारे ऋणों का एक अंश भाटे के वित्त-व्यवस्था का सूचक है, लोगों की ऐच्छिक बचतों के संग्रह का नहीं। यदि हमें भविष्यवस्था में मुद्रा-बाहुल्य की शक्तियों के प्रभाव को निश्चित रूप से कम करना है, तो इस प्रकार की भाटे की वित्त-व्यवस्था को भी आवश्यक रूप से कम किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि बिलकुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस कारण, हमें केन्द्र और राज्यों द्वारा भविष्य में ऋण लिये जाने के अपने कार्य-क्रम वास्तविक बचतों की प्राप्ति के यथार्थ अनुमान के आधार पर तैयार करने पड़ेंगे। साथ ही इस बात का प्रयत्न करना पड़ेगा कि छोटी बचतों के रूप में और बाजार प्रतिभूतियों (मार्केट सिक्योरिटी) की खरीद के रूप में लोगों से अधिक धन राशियाँ प्राप्त हों। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने पिछले वर्ष ब्याज की दरों को काफी हद तक बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं। मेरा विचार है कि नयी श्रेणी के ऐसे अल्प-बचत-पत्र जारी कर जिन पर ब्याज की दर मौजूदा दर से अधिक हो। इन नये अल्प-बचत-पत्रों से प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर लगाया जायगा। वर्तमान बचत-पत्र भी, जिनके ब्याज पर कर नहीं लगाया जाता, जारी रखे जायेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि ऐसे बचत-पत्र जारी किए जायें जिन पर दिये जाने वाले ब्याज पर भले ही कर लगा दिया जाय, पर ब्याज की दर ऊँची हो, तो छोटी और मध्यम आय वाले लोगों को, जिनकी कर सम्बन्धी देनदारी कम या दरमियानी है, बचत करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

14. बैंकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋणों में, अधिक कामकाज के चालू मौसम में, पिछले मौसम के इन्हीं महीनों की अपेक्षा, कुछ कम वृद्धि हुई है, लेकिन अधिक कामकाज के चालू मौसम के कई सप्ताह अभी बाकी हैं। मेरा अनुमान है कि रिजर्व बैंक ने दस दिन पहले जिन उपायों की घोषणा की है वे आगामी सप्ताहों में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की वृद्धि को सीमित रखने का काम करेंगे। बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में इस वर्ष के कम कामकाज के मौसम में इतनी अधिक कमी होनी चाहिए कि सारे वर्ष में इन ऋणों में कुल उतनी ही वृद्धि हो जितनी बढ़ते हुए उत्पादन की आवश्यकता के लिए काफी हो। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में अबतक मुद्रा-वृद्धि वास्तविक उत्पादन की वृद्धि से अधिक हुई है। इस स्थिति को और आगे जारी नहीं रहने दिया जा सकता। भविष्य में बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों में होने वाली वृद्धि को इतना सीमित रखना पड़ेगा, कि मुद्रा-उपलब्धि की वृद्धि उससे अधिक न हो जितनी उत्पादन की वृद्धि के वास्तविक अनुमान की दृष्टि से आवश्यक हो।

15. राज्य सरकारों को भी देश में राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी अनुशासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करना है। कुछ राज्यों के अगले वर्ष के बजटों में, जो अबतक पेश हो चुके हैं, घाटा दिखाया गया है। मेरा विचार है कि राज्य सरकारों से बातचीत करके यह निश्चित कर लूं कि राज्य सरकारों के काम, मुद्रा-बाहुल्य को रोकने की हमारी नीति के सामान्यतः अनुरूप हैं।

16. माननीय सदस्यों को मालूम है कि देश में ऐसी आमदनी और सम्पत्ति होने के कारण, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता, मुद्रा-सम्बन्धी उचित प्रबन्ध कुछ समय से कठिन हो गया है। यही बेहिसाबी आमदनी और सम्पत्ति जो कर न भ्रदा करने और मूल्य-नियंत्रण के नियमों को तोड़ने से प्राप्त होती है, सट्टेबाजी और सामान्यतः माल तथा सम्पत्ति के मूल्यों के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। तलाशियां लेने, नियमों को और ज्यादा कड़ाई से अमल में लाने और अधिक कठोर दण्ड देने आदि के जो उपाय हम कर चुके हैं उनके अलावा कुछ और भी ऐसे उपाय करने का मेरा विचार है जिनसे मौजूदा बेहिसाबी आमदनी और सम्पत्ति के कारण होनेवाली खराबियों को काफी हद तक कम किया जा सके और भविष्य में ऐसी आमदनी और सम्पत्ति प्राप्त करने की गुंजाइश और प्रलोभन कम हो जाय। मैं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी करना चाहता हूं जिनसे गहरी सम्पत्ति में अत्यधिक धन लगाने के लिए बढ़ावा न मिले, क्योंकि यह सम्पत्ति अधिक उत्पादक कार्यों के लिए यथेष्ट साधन उपलब्ध होने में बाधक होती है।

17. मैंने 17 फरवरी की सभा में जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी हमारी बहुत ही कठिन स्थिति का कुछ विस्तार से जिक्र किया था। उस अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से इतनी अधिक रकम निकाली गयी है कि अब यदि उसमें से थोड़ी सी भी और निकालनी पड़ी, तो स्थिति चिन्ताजनक हो जायगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस प्रारक्षित निधि की रकम में कुछ वृद्धि हो। हमने कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भर रहना बहुत कम कर दिया है। हाल के वर्षों में हमारा निर्यात भी कुछ सन्तोषजनक रहा है। फिर भी, चूंकि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की रकम बढ़ाना और विकाशील अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक आयात करना जरूरी है, इसलिए निर्यात में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता ज्यों-की-त्यों बनी हुई है।

18. हमें मित्र देशों की सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से काफी सहप्रयत्न मिल रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य हमारे विदेशस्थ मित्रों के प्रति, उनकी सहायता के लिए, एक बार फिर आभार प्रकट करने में मेरा साथ देंगे। विश्व बैंक द्वारा संगठित भारत सहायता संघ ने तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिए पिछले वर्ष 10280 लाख डालर की और रकम देने का वचन दिया था। इस सहायता का काफी बड़ा अंश विशिष्ट प्रायोजनाओं से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि विदेशों से सामान्य सामग्री, संघटक (कम्पोनेण्ट) और फालतू पुरजे मंगाने के उद्देश्य से दिया गया है। इस प्रकार की सहायता शोधन-सन्तुलन-सम्बन्धी हमारी वर्तमान कठिनाइयों में हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है और मुझे पूरी आशा है कि अगले वर्ष हमें भारत सहायता संघ से जो सहायता मिलेगी उसमें ऐसे प्रयोजनों के लिए और अधिक धनराशियां होंगी जिनसे शोधन-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में तुरन्त सुधार हो सकेगा। भारत सहायता संघ से पूछूँ हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल०-480 सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज और अन्य कृषि-पदार्थों के आयात के लिए उदारतापूर्वक सहायता मिली है। जो देश भारत सहायता संघ के सदस्य नहीं हैं उन्होंने भी हमें, 1964 में अतिरिक्त सहायता

की है। अभी हाल में हमने सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ से बोकारो के इस्पात के कारखाने के लिए एक करार किया है। आस्ट्रेलिया से 150,000 टन गेहूं का जो दान हमें मिला है और जिसकी घोषणा कुछ ही दिन पहले की गयी है उसका उल्लेख किये बिना भी मैं नहीं रह सकता। यह उदारतापूर्ण और सामयिक कार्य मेरे लिए विशेष सन्तोष का विषय है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह दो राष्ट्रमण्डल देशों के बीच बढ़ते हुए सहयोग का शुभ लक्षण है।

19. विदेशी सहायता के उपयोग की गति काफी बढ़ गयी है और अब उसका उपयोग प्रायः उसी गति से हो रहा है जिस गति से नयी सहायता के वचन मिल रहे हैं। फिर भी चालु पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में जिस सहायता का वचन हमें मिला है उसका कुछ भाग आवश्यक रूप से चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए आगे ले जाया जायेगा। हम इस समय इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि हमें चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। हमें आशा है कि हम मित्र देशों की सरकारों और संस्थाओं से हमारी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक सीमा तक पूरा करने के अग्रिम वचन प्राप्त करने के लिए अगले वर्ष ही बातचीत प्रारम्भ कर देंगे। विदेशी सहायता के इस प्रकार के अग्रिम आयोजन के आधार पर ही, हम विकास के क्रम को बाधा रहित रखते हुए चौथी पंचवर्षीय आयोजना को विश्वासपूर्वक प्रारंभ कर सकेंगे।

20. हम छोटे पैमाने पर अन्य विकासशील देशों की सहायता करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, हम अगले वर्ष नेपाल को अनुमानतः 8.5 करोड़ रुपये की सहायता और सिक्किम और भुटान को 6.2 करोड़ रुपये की सहायता देंगे। हमने कई अफ्रीकी देशों में चीनी, सूती कपड़े, सीमेंट और वनस्पति तेल आदि के कारखाने खोलने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने में सहायता पहुंचाने का भी प्रयत्न किया है। अगले वर्ष दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के देशों की तकनीकी सहायता के लिए 46 लाख रुपये की और संयुक्त राष्ट्र संघ के तकनीकी सहायता के परिवाहित कार्यक्रम के लिए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष प्रायोजना निधि में अंशदान देने के लिए 1.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का हमारा विचार है।

21. हमारी विकास-सम्बन्धी आयोजनाओं में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी का क्या स्थान हो, इस विषय में हाल के महीनों में भारत में बहुत विचार-विमर्श हुआ है। हम काफी समय से इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि मित्र देशों की सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो सहायता मिल रही है उसके अत्यावश्यक पूरक (सप्लीमेंट) के रूप में ही नहीं, बल्कि हमारे देश में तकनीकी कुशलता और उद्यम का शीघ्रता से विकास करने के लिए भी गैर-सरकारी विदेशी पूंजी से महत्वपूर्ण योग मिल सकता है। इस कारण हमने भारत के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सहयोग से गैर-सरकारी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया है। निवेश बढ़ाने के लिए हमने भारतीय उद्यम को जो प्रोत्साहन और सुविधाएं दी हैं वे सभी गैर-सरकारी विदेशी उद्यम को समान रूप में प्राप्त हैं और हम विदेशी निवेशकों को लाभ की रकम अपने देश में ले जाने की प्रत्येक सुविधा प्रदान करते हैं। उदारतापूर्ण और उचित व्यवहार की यह नीति भविष्य में जारी रहेगी। और हमारी सामान्य नीतियां—चाहे वे कर लगाने, उद्योगों के लिए लाइसेंस देने या मूल्यों का नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में हों—ऐसी होनी चाहिएं जो उद्यम और गति के प्रत्येक सम्भाव्य स्रोत को—चाहे वह देशी हो या विदेशी, सरकारी हो या गैर सरकारी, शीघ्र आर्थिक विकास के कार्य में नियोजित करने की हमारी इच्छा से मेल खाती हों।

22. चौथी पंचवर्षीय आयोजना की पूर्ति के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी रकमें पूंजी के रूप में लगानी पड़ेंगी। इसके लिए साधनों को जुटाने की पहली और सबसे आवश्यक बात यह है कि वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी स्थिरता का वातावरण बनाये रखा जाय। तभी अपनी इच्छा से पैसा बचाने के लिए बढ़ावा मिल सकेगा जिसे उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकेगा। इसी तरह कर लगाने की हमारी नीतियों में भी कुछ हद तक स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। मांग और सम्भरण (सप्लाई) की स्थिति के अनुसार अप्रत्यक्ष करों की दरों में प्रतिवर्ष-उपयुक्त परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है, किन्तु प्रत्यक्ष करों के ढांचे में अधिक मात्रा में स्थिरता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सम्बन्ध बचत और निवेश सम्बन्धी दीर्घकालीन निर्णयों से है। इस वर्ष के मेरे बजट प्रस्ताव इसी दृष्टि से तैयार किये गये हैं कि कम से कम उनसे इस लक्ष्य की आंशिक पूर्ति तो ही हो सके। कम से कम मैं यह नहीं समझता कि अधिक साधन जुटाने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए साधन जुटाने के लिए जो भी व्यवस्था हमारे लिए जरूरी है उसे, आयोजना का आरम्भ करने से पहले, उसके सभी आवश्यक उत्पादनों के साथ, स्थापित न करने का कोई कारण नहीं है।

23. अतः, यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले साधन, करों, बचत-संग्रह, या पर्याप्त लाभ की प्राप्ति के द्वारा उपलब्ध होनेवाले साधन सब एक ही कोश के अलग-प्रलग अंग हैं। हम इस बात की आशा नहीं कर सकते कि हम किसी खास स्रोत से तो अधिक मांग कर लें और दूसरे स्रोतों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े या एक काम में अधिक साधन लगा दें और दूसरे कामों के अग्रगण्य साधनों पर इसका प्रभाव न पड़े। अधिक उत्पादन और खर्च का निरन्धन, आय का निवारण और दुर्लभ साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग ये ही अतः बचत और निवेश में वृद्धि करने के साधन हैं। इसलिए बजट-सम्बन्धी नीति, केवल या मुख्यतः आमदनी और खर्च को बराबर करके दिखाने का प्रक्रिया नहीं है। निःसन्देह यह बहुत ही आवश्यक है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था का सहारा ही न लिया जाये या उसे निरपेक्ष सीमाओं के भीतर रखा जाय। पर जिस स्तर पर बजट संतुलित किया जाता है और जिस ढंग से यह सन्तुलन प्राप्त किया जाता है उस स्तर और उस ढंग का बचत और निवेश से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रगति से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है।

24. अगले वर्ष के बजट अनुमान, जिनका उल्लेख अब मैं करने जा रहा हूं, इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं। राजस्व खाते से 2116 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 117 करोड़ रुपया अधिक है। करों की मौजूदा दरों के आधार पर जिनमें आयातित वस्तुओं पर लगने वाला 10 प्रतिशत का वह अधिभार (सरचाज) भी शामिल है जिसकी घोषणा मैंने दस दिन पहले की थी, कुल राजस्व 2353 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। इस तरह राजस्व-अधिशेष 237 करोड़ रुपया होगा- अर्थात् चालू वर्ष की अपेक्षा 8 करोड़ रुपया अधिक।

25. राजस्व-व्यय के कुल 2116 करोड़ रुपये के अगले वर्ष के खर्च में 749 करोड़ रुपया रक्षा-सेवाओं के लिए होगा। यह चालू वर्ष की अपेक्षा 32 करोड़ रुपया अधिक है। किन्तु रूपयों में किया जाने वाला वास्तविक व्यय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सामान और वायुयानों की खरीद, जिन की कुल कीमत व्यय-अनुमान में शामिल कर ली गयी है, विलम्बित अदायगी की शर्तों के आधार पर की जा रही है। असैनिक (सिविल) शीर्षकों के अन्तर्गत 1367 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है जो चालू वर्ष से 85 करोड़ रुपया ज्यादा है। यदि उन रकमों को, जो पी० एल०-480 के अनुदानों के सम्बन्ध में विशेष विकास निधि को अन्तर्गत कर दी गयी हैं, हिसाब में न लिया जाय तो अतैनिक

शीर्षकों के अन्तर्गत वास्तविक वृद्धि बहुत अधिक हो जायगी। वृद्धि के मुख्य भाग का कारण ऋण चुकाने के लिए 38 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को सहायक अनुदान देने के लिए 39 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रशासनिक सेवाओं के लिए 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था, खासकर 'पुलिस' शीर्षक के अन्तर्गत, और सामाजिक तथा विकास-सम्बन्धी सेवाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

26. राजस्व में अगले वर्ष 125 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। यहां भी, अगर अपने आप सन्तुलित होने वाले पी० एल० — 480 के अनुदानों को छोड़ दिया जाय, तो वास्तविक वृद्धि और भी अधिक होगी। पहले की तरह, अधिकांश वृद्धियां राजस्व के प्रधान शीर्षकों के अन्तर्गत हुई हैं : 70 करोड़ रुपया आय और निगम कर के अन्तर्गत, 54 करोड़ रुपया केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों के अन्तर्गत और 20 करोड़ रुपया सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत। इसके अलावा, राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से मिलने वाले ब्याज और रिजर्व बैंक के अतिरिक्त लाभों में 39 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

27. पूंजी-परिव्यय (केपिटल आउटले) के लिए, जिस में राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों को छोड़ कर दूसरे सभी ऋण शामिल हैं, 114 करोड़ रुपये की व्यवस्था का अनुमान है, जो चालू वर्ष की व्यवस्था से 104 करोड़ रुपया अधिक है। इस का मुख्य कारण सड़कों के लिए 24 करोड़ रुपये की पहले से बड़ी व्यवस्था, अनाज की खरीद के लिए 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था, परमाणु-शक्ति के लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था, रक्षा सेवाओं के लिए 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था और औद्योगिक विकास बैंक के लिए 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। राज्य सरकारों और संघीय राज्यक्षेत्रों को ऋणों के रूप में 712 करोड़ रुपया दिये जाने का अनुमान है। यह रकम प्रायः चालू वर्ष की रकम के बराबर है। किन्तु आयोजना-सम्बन्धी सहायता के ऋणों की रकम 28 करोड़ रुपया अधिक होगी और अर्थोपाय (वेज ऐण्ड मीन्स) ऋणों की रकम उसी अनुपात में कम।

28. अगले वर्ष केन्द्र और राज्यों का कुल आयोजना-परिव्यय (खर्च) 2225 करोड़ रुपया होगा, जो चालू वर्ष के बजट में दिखाये गये 1984 करोड़ रुपये के आयोजना-परिव्यय से 241 करोड़ रुपया अधिक है। राज्यों की आयोजनाओं का खर्च 1027 करोड़ रुपया और केन्द्रीय आयोजना का 1198 करोड़ रुपया होगा। राज्यों के कुल खर्च का 650 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता से और 377 करोड़ रुपया खुद राज्यों के साधनों से दिया जायगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि केन्द्रीय आयोजना आंशिक रूप से रेलों, डाक और तार विभाग, हिन्दुस्तान स्टील और गैरसरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के आन्तरिक साधनों के 160 करोड़ रुपये से वित्त-पोषित की जायगी। इसलिए, इस सीमा तक केन्द्रीय सरकार के अनुमानों में धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 1688 करोड़ रुपए के लिए व्यवस्था, जिसमें से 300 करोड़ रुपया राजस्वखाते और राज्यों की सहायता का है, बजट में कर दी गयी है। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि रेलों, डाक और तार विभाग तथा गैरसरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 160 करोड़ रुपए के अंशदान में, चालू वर्ष के अंशदान से 45 करोड़ रुपया अधिक है। जब गैरसरकारी क्षेत्र के और अधिक उद्यम उत्पादन करने लगेंगे और उन में अतिरिक्त लाभ होने लगेगा तो बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना वे अर्थ-व्यवस्था के विकास में और अधिक योग देने में समर्थ हो सकेंगे।

29. इस आवश्यकता का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ कि सरकारी ऋणों को उतना ही रखना चाहिए जितना वास्तविक बचतों के आधार पर वे मिल सकते हों। इस सिद्धान्त के आधार पर मैंने अगले वर्ष सरकारी ऋणों के लिए 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जबकि चालू वर्ष के लिए 293 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इसी कारण, छोटी बचतों से होने वाली प्राप्तियों को, चालू वर्ष के स्तर पर, 135 करोड़ रुपया माना गया है। लेकिन विदेशी ऋणों से और भी अधिक प्राप्तियाँ होंगी और इनकी रकम 669 करोड़ रुपया रखी गयी है।

30. इस प्रकार अगले वर्ष की सम्पूर्ण स्थिति का सारांश यह है कि करों की मौजूदा दरों के आधार पर, राजस्व खाते में 237 करोड़ रुपए का अधिशेष रहेगा। पूँजी खाते से किया जाने वाला 2094 करोड़ रुपए का कुल वितरण, जिस में ऋण की अदायगी का 267 करोड़ रुपया शामिल है, राजस्व-अधिशेष के अलावा, 939 करोड़ रुपये के देशी और विदेशी ऋणों, छोटी बचतों से प्राप्त 135 करोड़ रुपये, ऋण की वापसी के 334 करोड़ रुपये, पी० एल०—480 निधि के 191 करोड़ रुपये के निवेश, वार्षिकी जमा-पत्रों के 65 करोड़ रुपये और 'विविध ऋण और जमा' शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त 203 करोड़ रुपये से पूरा किया जायगा। सब मिलाकर, माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कई वर्षों में पहली बार, करों की मौजूदा दरों के आधार पर अगले साल के बजट में 10 करोड़ रुपये का थोड़ा सा अधिशेष रहने का अनुमान है।

31. माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि अगले वर्ष के लिए कुछ अधिशेष की घोषणा करने के बाद, मैं बजट को यो ही रहने दे कर अपने स्थान पर क्यों नहीं बैठ जाता। किन्तु यह आवश्यक है, खासकर चौथी आयोजना से ठीक पहले, कि हम करों के सारे ढांचे पर अच्छी तरह से नज़र डालें और उसमें ऐसा समन्वय अथवा परिवर्तन करें कि इच्छित लाभ होने लगे। और जो प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उनमें मैंने यही करने का यत्न किया है।

अप्रत्यक्ष कर

32. अप्रत्यक्ष करों के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं—राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना और मूल्य-नीति के साधन के रूप में काम करना। जिन अप्रत्यक्ष करों का मुख्य उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना है उन का समन्वय न केवल राजस्व-सम्बन्धी आवश्यकताओं की दृष्टि से, बल्कि व्यक्तिगत नागरिक के बजट पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की दृष्टि से किया जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मौजूदा परिस्थिति में, जबकि बढ़े हुए मूल्यों ने जनता के एक वर्ग पर बोझ डाल रखा है, उन क्षेत्रों में कुछ राहत पहुँचाने की आवश्यकता है जहाँ सम्भरण (सप्लाई) स्थिति ऐसी है कि हर कोई उचित रूप से यही आशा करेगा कि उपभोक्ता को राहत पहुँचायी जाय। साफ है कि राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में बहुत अधिक राहत नहीं दी जा सकती। और न उन क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष करों में कमी की जा सकती है जहाँ आयदातों में कमी करने या आयदातों के लिए पहले की बनिस्बत ज्यादा माल दिये जाने की दृष्टि से चीजों की खपत पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

33. एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जहाँ विभिन्न स्तरों पर तंगी मौजूद हो, मूल्यों के ढाँचे में बिगाड़ पैदा हो जाने की प्रवृत्ति आ जाती है। यह बात सभी को मालूम है कि जो वस्तुएँ दुर्लभ सामग्री से बनायी जाती हैं, चाहे वह सामग्री विदेशों से मंगायी जाती हो या देश में मिलती हो, उन की बिज्जी से बहुत ज्यादा नफा उठाया जाता है, और इस फालतू नफे को हस्तगत करने के लिए मैं विदेशों से मंगायी जानेवाली और देश में बनेवाली कुछ खास-खास चीजों के शुल्कों में वृद्धि करना चाहता हूँ। प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करनेवालों में दुर्लभ सामग्री का वितरण करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम मजबूत बनाना चाहते हैं। पर इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि वितरण

पर हमेशा ही उस हालत में पूरा-पूरा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता जिसमें सभी अन्तिम उपभोक्ताओं (एण्ड-यूजर) की आवश्यकताओं को एक केन्द्रीय अभिकरण (एजेंसी) की मार्फत पूरा किया जाता हो। और न मूल्य-व्यवस्था से उस सीमा तक बचने का कोई कारण है, जिस सीमा तक वितरण व्यवस्था की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जा सकता हो। इसलिए जो कुछ करना मैंने आवश्यक समझा है वह यही कि उन क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दी जाय जहां यह मूल्यों के ढांचे को मौजूदा बिगाड़ को ठीक कर सकती हो, और कुछ फालतू नफे को हस्तगत कर लूं और इस व्यवस्था से जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो उसका उपयोग उपभोक्ता को उस सीमा तक राहत पहुंचाने में किया जाय जहां तक ऐसा करना सम्भव हो।

34. अप्रत्यक्ष करों में रियायतें देने के मेरे प्रस्तावों का सम्बन्ध केवल उत्पादन शुल्कों से है। जूतों, साइकिल के हिस्सों (पार्ट्स), साइकिल-टायरों और ट्यूबों और पंजीकृत (रजिस्टर्ड) दैनिक समाचार पत्रों (जिनमें उनके साप्ताहिक संस्करण भी शामिल हैं) के प्रकाशन में इस्तेमाल किये जाने वाले छापने और लिखने के कागज पर से उत्पादन शुल्क हटा देने का मेरा विचार है। मटमैले (ग्रे) और परिष्कृत (प्रोसेस्ड) मोटे तथा दरमियानी सूती कपड़े की जिन किस्मों के मूल्य पर नियंत्रण लगा है उन के शुल्क की प्रभावी दरों में 50 प्रतिशत की कमी, बनास्पती (वेजिटेबिल प्रोडक्ट) पर लगे शुल्क में 50 प्रतिशत की और छापने तथा लिखने के सस्ती किस्म के कागज और टाइप करने तथा अनेक प्रकार से काम में लाये जाने वाले कागज की कई दूसरी किस्मों पर लगे शुल्क में 30 प्रतिशत की कमी करने का विचार है। दूसरे कारणों से अपेक्षाकृत मोटे और तेल पर आधारित औद्योगिक इकाइयों (डेनोर) वाले रेयन के तागे, सेलूलोज ड्रय से बने रेशे और, सीमान्तिक रूप से, स्टेपल रेशे से बने तागे के शुल्क में भी कमी करने का मेरा प्रस्ताव है। बहुत ही कम राजस्व प्राप्ति के कारण कुछ और चीजों, जैसे कि रेशमी कपड़े, ग्रामोफोन, सिगारों और चांदी पर लगे शुल्कों को भी हटा देने का विचार है। इन कमियों से राजस्व में 1965-66 में 29.5 करोड़ रुपये की कमी हो जायगी।

35. मैंने ये कमियां सामान्य रूप से उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं पर लगे शुल्क में की हैं, क्योंकि मुझे आशा है कि इस का लाभ उपभोक्ता अर्थात् इन वस्तुओं का उपयोग करने वाले को प्राप्त होगा। यदि यह आशा पूरी न हुई तो वर्ष के अन्तर ही शुल्कों को फिर से लागू करना जरूरी हो जायगा। इसी लिए प्रस्तावित कमियां शुल्क की सांविधिक (स्टेट्यूटरी) दरों में कमी कर के नहीं, बल्कि सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारों के अनुसार अधिमूचना प्रकाशित करके की जा रही है।

36. उत्पादन शुल्क में रियायतें देने के लिए चीजों का चुनाव करते हुए मैंने मिट्टी के तेल (किरासिन) पर लगे शुल्क में कमी करने के सम्बन्ध में खास तौर से विचार किया है। लेकिन मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हम मिट्टी के तेल पर लगे शुल्क में कमी न कर सकेंगे, क्योंकि बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों में से यह एक बहुत बड़ी मद है। इसके अलावा, इस समय भी, मिट्टी के तेल पर लगा शुल्क इतना कम है कि उससे लारियों में और गैर-घरेलू कामों के लिए इसके इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है। और इन्हीं कामों के लिए मिट्टी के तेल के और ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देने से कोई लाभ न होगा।

37. इस अवसर से लाभ उठाकर मैं उत्पादन शुल्कों, मुख्यतः सिगरेटों और टायरों से सम्बन्ध रखने वाले शुल्कों में भी कुछ प्राविधिक समायोजन (टेक्निकल एडजस्टमेंट) कर रहा हूँ। उत्पादन की वर्तमान प्रणाली के आधार पर, इन परिवर्तनों से, सिगरेटों से प्राप्त होने वाले राजस्व में 40 लाख रुपये की और टायरों से प्राप्त होने वाले राजस्व में 35 लाख रुपये की वृद्धि होगी। मुझे विश्वास है

कि सम्बद्ध उद्योग, इन चीजों के मूल्य पर किसी तरह का सम्पूर्ण प्रभाव डाले बिना, इन छोटी छोटी प्राविधिक वृद्धियों को बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने शुल्कगत वस्तुओं के प्रकार और छूट के परिमाण में कुछ और छोटे छोटे परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है। राजस्व की दृष्टि से इन परिवर्तनों का विशेष महत्व नहीं है।

38. कई दुर्लभ सामग्रियों के वितरण और उन से बनी वस्तुओं की बिक्री से अधिक लाभ उठाया जा रहा है, इसलिए उत्पादन शुल्कों में वृद्धियां करके इन वस्तुओं से होने वाले अतिरिक्त लाभ के कुछ अंश को मैं प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। कच्चे तांबे और मिश्र तांबे के उत्पादन शुल्क को 300 रुपये प्रति मेट्रिक टन से बढ़ा कर 1,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन कर देने और चक्कों (सकिल) तथा चद्दरों (शीट) आदि के शुल्क को 500 रुपये प्रति मेट्रिक टन से बढ़ा कर 1,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन कर देने का मेरा विचार है। इस्पाती डलो, प्लेटो, और रेलों तथा स्लीपर की छड़ों के शुल्क में 10 रुपया प्रति मेट्रिक टन की, आधी-फिनिश की हुई चीजों और छड़ों, डण्डों (राड) और इमारती काम की लोहे की चीजों के शुल्क में 15 रुपये प्रति मेट्रिक टन की, काली चद्दरों (ब्लैक शीट) और छल्लों (हूप) के शुल्कों में 40 रुपये प्रति मेट्रिक टन की, दृढ़ बनाने की नरम इस्पाती पट्टियों (स्केल्प) के शुल्क में 50 रुपये प्रति मेट्रिक टन की, पट्टियों (स्ट्रिप्स) के शुल्क में 90 रुपये प्रति मेट्रिक टन की और जस्ती प्लेटों व चद्दरों के उत्पादन शुल्क में 100 रु० प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि कर देने का मेरा विचार है। तीन कालेटी और तीन की चद्दरों के प्रभावी शुल्क को 165 रु० से बढ़ा कर 225 रु० प्रति मेट्रिक टन कर देने का भी प्रस्ताव है। इन समूह पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि कर देने से 15.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी।

39. सूती कपड़ा बनाने वाले बिजली के करबों के छोटे कारखानों के लिए निर्धारित थोक शुल्कों की वर्तमान व्यवस्था को मैं और भी सरल बनाना चाहता हूँ। बहुसंख्य कारखानों को, जिनमें प्रत्येक में पाच से कम करबे हैं, जो कुल छूट मिलती है उसकी जगह 25 रुपया प्रति करबा प्रति वर्ष का थोड़ा सा थोक शुल्क लगाया जा रहा है। विखण्डनविरोधी (एण्टी ब्रैगमेटेशन) अर्थात् कारखाने को टुकड़ों में बाटने की रोकथाम करने वाले उपबन्ध को भी नये सिरे से लिखा जा रहा है।

40. उत्पादन शुल्कों में इन सभी परिवर्तनों से 1965-66 में राजस्व में 13 करोड़ रुपये की वास्तविक कमी होगी।

41. उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होनेवाला राजस्व 1955-56 में 145 करोड़ रुपये था जो क्रमशः बढ़ते हुए 1964-65 में लगभग 773 करोड़ रुपये होगया। यह कुछ संतोष की बात है कि कई वर्षों में पहली बार, कुल राजस्व में कोई खास कमी किये बगैर हम उपभोक्ता को कुछ राहत देने में समर्थ हुए हैं।

42. दस दिन हुए मैंने विदेशों से मंगायी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के 10 प्रति शत के बराबर का विनियमनकारी (रेगुलेटरी) सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की थी। वर्तमान परिस्थितियों में यह शुल्क जारी ही रहना चाहिए। इसके अलावा, कुछ मामलों में जहां जहाज से उतरते (लैंडिंग) मूल्यों और मौजूदा बाजार दरों में भारी अन्तर है वहां मौजूदा दरों में वृद्धि करना आवश्यक है। इसलिए मैं स्टेनलेस स्टील की प्लेटों और चद्दरों के आयात शुल्क को मूल्यानुसार 30 प्रति शत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत और जहां प्रति मेट्रिक टन 20 रुपये की मौजूदा तरजीह लागू होती है वहां इसे जारी रखते हुए इस्पाती तीन की चद्दरों के शुल्क को 100 रुपया प्रति मेट्रिक टन घन (प्लस) 5 प्रति शत से बढ़ा कर 325 रुपया प्रति मेट्रिक टन कर देना चाहता हूँ। यह भी प्रस्ताव है कि सेलुलोज रहित नकली रेशम (नान सेलुलोजिक आर्टिसिल्क) के तागे और धागे के शुल्क को 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम या 55 प्रतिशत से जो भी अधिक हो, बढ़ाकर 10.25 रुपये प्रति किलोग्राम या 75 प्रतिशत, जो

भी अधिक हो, कर दिया जाय। रंग लेप (पेण्ट), रंग (कलर) और रंगलेप सम्बन्धी वस्तुओं के, जिनका अन्यथा उल्लेख न हो, शुल्क को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत मोडियम हाइड्रोमल्काइट के शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत, गंध सार तेलों और सुगन्धित द्रव्यों के, जिनका अन्यथा उल्लेख न हो, शुल्क को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत और कागज के जिसका अन्यथा उल्लेख न हो, पर जिसमें अखबारी कागज और छापने व लिखने का कागज शामिल नहीं है, शुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर देने का मेरा विचार है। कपास के सांविधिक (स्टेट्यूटरी) आयात शुल्क बढ़ाकर को 50 पैसे प्रति किलोग्राम कर देने का भी मेरा विचार है। ताकि साल के अन्दर जरूरत पड़ने पर, प्रभावी शुल्क में वृद्धि कर सकू। अधिभार सहित आयात शुल्कों की वृद्धियों से 1965-66 में 6—5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस के अलावा, इस्पानी टीन की प्लेटों, लोहे और इस्पात की चीजों और तांबे के प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टर-वैलिंग) शुल्क के परिणामस्वरूप राजस्व में 8 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। सीमा शुल्कों से कुल 14.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

43. अप्रत्यक्ष करों में जो परिवर्तन होंगे उन्हें अस्थायी कर संग्रह अधिनियम (प्रावीजनल कन्वैशन आफ टैक्सेज ऐक्ट) के अधीन तत्काल लागू किया जायेगा। सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क को मिला कर, इन परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि 1965-66 में राजस्व में 1.5 करोड़ रुपये की थोड़ी सी वृद्धि हो जायगी।

निर्यात-प्रोत्साहन

44. माननीय सदस्यों को मानूँ मैं कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर सम्बन्धी राहत देने के लिए इस समय कई व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बंध में जो राहत दी जा रही है वह शुल्क की वापसी के रूप में होती है। हमारी अर्थव्यवस्था जैसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, जिसमें सब स्तरों पर कमी रहती है और उस कमी के कारण उत्पादन की लागत बढ़ती है, निर्यात-सम्बन्धी नये उद्योगों को जिन कठिनाइयों का अनुभव होता है उनका विचार करके हम इन उद्योगों को रेल भाड़े और लाभ पर कर लगाने के सम्बन्ध में भी कुछ राहत देते हैं।

45. हमारे निर्यात सम्बन्धी उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने के ये प्रयत्न निर्यात को बढ़ाने में कुछ सफल तो हुए हैं, पर निर्यात को जाने वाली, अन्तिम रूप से तैयार वस्तु के निर्माण के काम आने वाले कच्चे माल और संधटकों पर लगे हुए अन्य करों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि निर्यात सम्बन्धी उद्योगों को विभेद के आधार पर कुछ और सहायता दी जाय। आज भारत में बिक्री कर और चुंगी जैसे बहुत से ऐसे कर लगाये जाते हैं जिनके सम्बन्ध में इस समय निर्यात के लिए कर में राहत नहीं दी जाती। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में जो कच्चा माल, संधटक और मध्यवर्ती पदार्थ काम आते हैं उन पर लगे हुए आयात-शुल्कों और उत्पादन-शुल्कों के कुछ अंश वापस करना कठिन है। सामान्यतः यह आवश्यक है कि निर्यात-सम्बन्धी उन नये उद्योगों की कठिनाइयाँ कम की जायँ जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता की दृष्टि में अपनी स्थिति अभी पूरी तरह से दृढ़ करनी है। इसलिए मैं निर्यातकों को उनके निर्यात के मूल्य के 15 प्रतिशत भाग तक के कर-जमा-पत्र देने का अधि-कार प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार की सहायता का ठीक ठीक परिमाण विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग होगा और वह ध्यानपूर्वक जाच करने के बाद निर्धारित किया जायेगा। कर-जमा-पत्र या तो करों की अद्वयगी के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं या उनका मूल्य कर-सम्बन्धी दायित्व से जितना ज्यादा हो उतनी सीमा तक उनकी रकम नकदी के रूप में वापस की जा सकती है।

46. माननीय सदस्यों को मालूम है कि संरक्षण-आयात-शुल्क लगाकर विदेशी प्रतियोगिता से विकासशील देशों के नये उद्योगों की रक्षा करने की आवश्यकता को विशेषज्ञ और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण बहुत समय से मानते आये हैं। विकास शील देशों के नये निर्यात को सहायता पहुंचाने की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक है और उसका आधार भी वही है। यह विचार अर्थशास्त्रियों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि हम निर्यात से होने वाली कमाई के लिए प्रत्यक्ष विनीय सहायता देने का अधिकार प्राप्त कर लें ताकि निर्यात को बढ़ाने के हमारे प्रयत्न अधिक प्रभावकारी और कुशलतापूर्ण हो सकें।

निगम कर

47. माननीय सदस्यों को पता है कि पिछले दो वर्षों से हमारे निगम करों के ढांचे में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। प्रधानतः साधनों में वृद्धि करने की सर्वोपरि आवश्यकता को देखते हुए ऐसा करने की आवश्यकता हुई थी। निगम करों की कठोरता को कम करने के लिये मैंने अपने पिछले बजट में बहुत से परिवर्तन किये थे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि भावना अब भी यही है कि भारत में निगम कर ऊंचे हैं और इनकी कुछ बातों से निगमित क्षेत्र (कारपोरेट सेक्टर) की प्रगति में बाधा पड़ती है। सांविधिक ग्रन्थ (स्टेट्यूट बुक) में दिये हुए विभिन्न करों के भार की मैंने सावधानी से छानबीन की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि निगम करों के वर्तमान ढांचे में उसकी अच्छी बातों में फेर बदल किये बगैर, कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, लाभांश कर (डिविडेंड टैक्स) की बहुत अधिक आलोचना की गयी है। अब तक के अनुभव से यही प्रकट हुआ है कि इसमें लाभांश के वितरण की प्रणाली में विशेष अन्तर नहीं आया। फिर भी, मैं यह सोच बिना नहीं रह सकता कि वर्तमान स्थिति में जबकि हमें अर्थ व्यवस्था से मुद्रा बाहुल्यकारी प्रभाव को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना है और निगमित क्षेत्र में निवेश करने के लिए पर्याप्त साधन जुटाने हैं, लाभांश-वितरण पर कुछ नियंत्रण बनाये रखने की आवश्यकता है। इसी तरह अतिकर (सर-टैक्स) के पूरे प्रभाव को जांचने का हमें अब तक काफी समय नहीं मिल सका, इसलिए निगम कर के इस खास पहलू में ज्यादा फेर बदल करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी, मैंने निगम करों की सामान्य योजना में कई परिवर्तन करने का निश्चय किया है जिन से, मुझे आशा है, निगमित क्षेत्र की कम से कम कठिनाइयां तो दूर हो ही जायेंगी।

48. जो उद्योग वित्त अधिनियम, 1964 की प्रथम अनुसूची के भाग iv में उल्लिखित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उन्हें कर सम्बन्धी कुछ लाभ प्राप्त होते हैं उस सूची में चूने के पत्थर, आग और टपकन को प्रभ वहीन करने वाली मोटरों, पिटवां लोहे और इस्पात की ढली वस्तुओं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और जहाजों को जोड़ कर मैं उसे परिवर्द्धित करना चाहता हूं।

49. मैंने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि धारा-104 की जो कम्पनियां पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से वस्तुओं का निर्माण अथवा उपयोगीकरण करती हैं या खानों में खुदाई कराती हैं या बिजली बनाती या उसका वितरण करती हैं या बिजली सम्बन्धी अन्य कार्यों में संलग्न हैं और जिनकी सारी आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है उन्हें पहले 2 लाख रुपये की आमदनी पर 50 प्रतिशत के हिसाब से कर देना पड़ेगा। अब मैं इस रियायत के दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। ऐसी सभी कम्पनियों पर—विदेशी कम्पनियों को छोड़ कर—मेरे प्रस्ताव के आधार पर उनकी आमदनी के पहले 10 लाख पर 50 प्रतिशत के हिसाब से कर लगेगा, भले ही उनकी कुल आमदनी चाहे जितनी हो। 104 धारा के अन्तर्गत, कुछ किस्म की कम्पनियों पर, लाभ न बांटने की अवस्था में 37 प्रतिशत के हिसाब से दण्ड लगता है। मैं इस दर को, व्यापारिक कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए घटा कर 25 प्रतिशत कर देना चाहता हूं। जहां तक उत्पादन करने वाली

कम्पनियों का सम्बन्ध है हमने उन्हें कुछ रियायतें दे रखी हैं ताकि वे पर्याप्त प्रारक्षित पूंजी खड़ी कर सकें। जो कम्पनियां व्यापार नहीं करती, अर्थात् वे कम्पनियां जो आंशिक रूप से उत्पादन के क्षेत्र में काम करती हैं, वे कम्पनियां जो विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करती हैं और वे कम्पनियां जो इमारती कामों में लगी हुई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि लाभों के अनिवार्य वितरण के 90 प्रतिशत उच्चतर सांविधिक प्रतिशत का उस दिशा में लागू किया जायेगा जब इकट्ठा हुआ लाभ और प्रारक्षित पूंजी, उनकी चुकता पूंजी और ऋण पूंजी या उनकी स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्य के तुल्य से भी ज्यादा हो जायेगी। अभी, जिस सार्वजनिक कम्पनी के 51 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर किसी दूसरी कम्पनी के पास होते हैं जिसमें जनता के काफी शेयर होते हैं या उस कम्पनी के होते हैं जो ऐसी कम्पनी की 100 प्रतिशत सहायक होती है, तो पहली कम्पनी को उस तरह की कम्पनी नहीं माना जाता जिसमें जनता के काफी शेयर हों। इस स्थिति में परिवर्तन करने और ऐसी कम्पनी को भी वैसी ही मानने का विचार है जिसमें जनता के काफी शेयर हों।

50. हमारे बहुत से बड़े-बड़े शहरों में भीड़-भाड़ का बढ़ना एक विकट समस्या बन गई है। इसलिए ऐसे शहरों से बड़े-बड़े कारखानों को किसी दूसरी जगह चले जाने को प्रेरित करने के लिये कुछ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसलिए सार्वजनिक कम्पनियों के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि इन शहरों में जमीन और इमारतों की बिक्री से जो पूंजीगत लाभ हो उसका कर उसी, सीमा तक वापस कर दिया जाये जिस सीमा तक किसी नये क्षेत्र में जमीन और इमारतों पर जिनमें कर्मचारियों के रहने के मकान भी शामिल हों, पहले से सरकार की मंजूरी लेकर, पूंजी लाभ कर को फिर से लगाया जाय।

51. मैं ने पिछले साल बताया था कि मैं आयकर अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी छूट का दर में संशोधन करना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि विकास सम्बन्धी छूट की सामान्य दर अब 20 प्रतिशत है। सुझाव दिया गया है कि यह छूट खास-खास चीजों के लिए दी जानी चाहिए और हमने कुछ सीमा तक खानों से कोयले की खुदाई करने की मशीनों और जहाजों के सम्बन्ध में ऐसा करने का यत्न किया है। अब मेरा प्रस्ताव है कि विकास छूट की प्रतिमानित दर में 15 प्रतिशत की कमी कर दी जाय जो उन उद्योगों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जो आयकर अधिनियम की नयी पांचवी अनुसूची में शामिल हैं। इस अनुसूची के उद्योगों को 25 प्रतिशत की विकास छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा। कोयले की खुदाई के काम आने वाली मशीनों और जहाजों के सम्बन्ध में यह छूट क्रमशः 35 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के हिसाब से जारी रहेगी। लेकिन जिन प्रतिष्ठानों के लिए अब इस दर में कमी की जा रही है वे भी 31 मार्च 1967 तक मौजूदा 20 प्रतिशत का लाभ उठाते रहेंगे।

52. अकसर कहा जाता है कि कम्पनियों पर लगने वाले आयकर और अतिकर का कुल भार बहुत ऊँचे स्तरों तक पहुँच जाता है जिससे निवेश रुक जाता है। मैं नहीं समझता कि बात ऐसी ही है, लेकिन इस सम्बन्ध में किसी भी तरह का भ्रम दूर करने के लिए आयकर बोर्ड-निर्गमों सम्बन्धी कर को छोड़ कर, किन्तु लगाये गये कर को मिलाकर—सामान्य शेयरों के लाभांश के वितरण को ध्यान में रखते हुए—और अतिकर की अधिकतम सीमा को, कम्पनियों की कुल आमदनी का 70 प्रतिशत रखने का मेरा विचार है। इस सीमा को आगे कर सम्बन्धी देनदारी की कुल रकम में जो भी अधिकता होगी उसे अतिकर में से बाद में दे दिया जायेगा, जो अन्यथा कम्पनी पर आरोपणीय होती है। यह व्यवस्था भारतीय कम्पनियों और किसी भी उस कम्पनी पर, जिसमें जनता के काफी शेयर होंगे, लागू होगी जो अपना लाभांश भारत के अन्दर घोषित करेगी।

53. निगमित क्षेत्र सम्बन्धी करों में जिन विभिन्न परिवर्तनों की रूपरेखा मैंने बतायी है उनसे कुछ सीमा तक इस क्षेत्र की वास्तविक कठिनाइयों में कमी हो सकेगी। उत्पादन की गति में तेजी लाने और उद्योग के विस्तार के लिए साधनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त अधिकार प्राप्त करने का मेरा विचार है। राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, राजस्व के वर्तमान स्रोतों का त्याग कर मैं ऐसा नहीं कर सकता। किन्तु वर्तमान निवेशों से हुई राजस्व-वृद्धि के कुछ अंश को औद्योगिक विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा करने और पहले से अधिक उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के काम में लाया जा सकता है। इसलिए मैं यह व्यवस्था करने के लिए अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ कि किसी भी उत्पादक इकाई (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) द्वारा जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उसके उस उत्पादन पर दिया जाये, जो आधार वर्ष (बेस इयर) में उसके द्वारा किये गये उत्पादन के अतिरिक्त हो उस के लिये उस उत्पादक इकाई को दिये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर कर-जमा-पत्र (टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट) दिये जायें। इसी तरह मैं यह व्यवस्था करने के लिए भी अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ कि किसी भी उत्पादक कम्पनी द्वारा, अधिकार को मिलाकर जो निगम कर उसके द्वारा आधार वर्ष में दिये गये तुल्य कर से अधिक मात्रा में दिया जाय उस के लिए अधिक मात्रा के 20 प्रतिशत के बराबर के कर-जमा-पत्र दिये जायें। इस पर सम्बद्ध वर्ष के सम्पूर्ण कर के 10 प्रतिशत की सीमा और लागू की जायेगी। इन जमा-पत्रों का उद्देश्य यही है कि इनका उपयोग उद्योग के विस्तार में सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों के लिए अर्थात् डिबेंचर ऋणों की अदायगी के लिए या स्वीकृत संस्थाओं से लिए गये ऋणों की अदायगी के लिए किया जाय।

54. सरकार ने हाल ही में एक चाय वित्त समिति की स्थापना की थी और उस समिति ने चाय कम्पनियों पर लगाने वाले प्रत्यक्ष कर में राहत देने के लिए कुछ सिफारिशों की थीं। उन सिफारिशों को संशोधित रूप में स्वीकार कर लेने का मेरा विचार है और आवश्यक उपबन्ध वित्त विधेयक में शामिल कर लिये गये हैं।

55. जो कम्पनियां अपने कर्मचारियों में परिवार-नियोजन हेतु अदायगियां करने का खर्च उठावेंगी उनके इस खर्च को ग्रामदानी की रकम में से घटा देने की अनुमति देने का मेरा विचार है। जहां यह खर्च पूंजी की तरह का होगा वहां इसे पांच वर्ष की अवधि में ग्रामदानी की रकम से घटा देने की अनुमति दी जायेगी।

व्यक्तिगत कर

56. अब मैं व्यक्तिगत करों के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैं अपने भाषण में, शहरी सम्पत्ति में, जिसके मूल्य में कई कारणों से बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, अत्यधिक निवेश को नियंत्रित करने की आवश्यकता का उल्लेख कर चुका हूँ। इस तरह के नियंत्रण के बिना अधिक उत्पादक कार्यों के लिए निवेश को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। यह मांग भी की जाती रही है कि शहरों में सम्पत्ति के विपुल संग्रह पर कोई अधिकतम सीमा लागू की जानी चाहिए। मैंने इस समस्या पर कई दृष्टियों से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि किसी राजस्व विषयक व्यवस्था के माध्यम से इस समस्या में निपटने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि इस प्रकार की सम्पत्ति पर अतिरिक्त सम्पत्ति कर लगाया जाय। यह कर एक लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की सम्पत्ति पर लागू होगा। विभिन्न प्रकार के शहरों की सम्पत्ति के मूल्यों में अन्तर होने के कारण मैंने 1 लाख और चार लाख के बीच, 4 लाख और 8 लाख के बीच, 8 लाख और 16 लाख के बीच, और 16 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों के लिए छूट की अलग-अलग सीमाएं निर्धारित करने की व्यवस्था की है। यह छूट इन

श्रृंखलाओं के सबसे छोटे शहर के लिए 2 लाख रुपये से लेकर सबसे बड़े शहर के लिये 5 लाख रुपये तक अलग-अलग होगी। माननीय सदस्य देखेंगे कि इस प्रयोजन के लिए शहरों का जो वर्गीकरण मैं ने अपनाया है वह वही है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पूरक और दूसरे भत्ते देने के उद्देश्य से पहले से मौजूद है। मेरे प्रस्ताव के अनुसार, जो शहरी सम्पत्ति छूट की इन सीमाओं से अधिक मूल्य की होगी उस पर बढ़ती हुई दरों के हिसाब से अतिरिक्त सम्पत्ति कर लगेगा। ये दरें ऐसी सम्पत्ति के कुल बाजार भाव के क्रमिक खण्डों पर एक प्रतिशत से चार प्रतिशत तक बढ़ती जायेगी। अभी मेरे लिये इस बात का बिल्कुल सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि इस मार्ग से कितना राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन 1965-66 के लिए मैं अतिरिक्त प्राप्ति की रकम को 1.5 करोड़ रुपया कूत रहा हूँ। यहां मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि इस कर का जितना उद्देश्य राजस्व-प्राप्ति है उतना ही व्यापक सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी। हो सकता है इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप सम्पत्ति के स्वामी अपन-सम्पत्ति को निगमित संस्थाओं में अन्तरित करने लगे जिन पर अभी सम्पत्ति कर नहीं लगता या फिर सम्पत्ति-स्वामिनी (प्रापर्टी ओनिंग) कम्पनियां खड़ी होने लगे। यदि ऐसी प्रवृत्ति पैदा हुई, तो सरकार उचित अवसर पर उस सम्बन्ध में भी कार्रवाई करेगी।

57. नयी औद्योगिक कम्पनियों ने सामान्य शेयरों में पैसा लगाने के लिए सम्पत्ति कर (वेलथ टैक्स) की अदायगी से छूट देने की व्यवस्था में फिर पांच वर्ष के लिए जारी कर रहा हूँ। यह रियायत उन्हीं कम्पनियों को मिलेगी जो 28 फरवरी 1965 के बाद पहली बार पूजी जारी करेंगी। जो कम्पनियां बोनस शेयर जारी करती हैं वे इन शेयरों के प्रत्यक्ष मूल्य पर 12- $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर देती हैं। स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति, उस के नाम जारी किये गये बोनस शेयरों पर पूजी-लाभ कर (कैपिटल गेन्स टैक्स) देता है, तो उन्हीं शेयरों पर कम्पनी द्वारा दिये गये कर का कुछ अंश पूजी-लाभकर सम्बन्धी उस की देनदारी को कम करने में लगाना चाहिये। इसलिए, मैं ऐसे शेयरों पर दिये जाने वाले पूजी-लाभ-कर में, बोनस शेयरों के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत केवल की छूट देना चाहता हूँ। जो इस कर की रकम तक सीमित होगी।

58. व्यक्तिगत आमदनियों पर लगने वाले करो के सम्बन्ध में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि करो के ढांचे को सरल बनाया जाये। एक कारण तो यही है कि आयकर और अधिकर (सुपर टैक्स) का अंतर कालान्तरण सम्बन्धी एक भ्रम है और आजकल जिस तरीके से हम विभिन्न कटौतियों की अनुमति देते हैं वह भी न तो सरलता की दृष्टि से ठीक है और न वास्तविक भार को समझने की दृष्टि से। अधिकर को आयकर में मिलाकर और दूसरे तरीकों से भी मैं ने करो के सारे ढांचे को सरल बनाने का यत्न किया है। इस से थोड़े समय के लिए राज-कोषीय प्राप्ति में कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन इससे कर सम्बन्धी प्रशासन में सुधार हो सकेगा और करो की देनदारी के सम्बन्ध में साधारण करदाता के रुख में परिवर्तन आयेगा।

59. बुनियादी तौर पर मैं ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करना चाहता हूँ जिस में आयकर के प्रयोजन के लिए मौजूदा निर्बाध छूट बन्द हो जायगी और इस तरह, अन्य बातों के साथ-साथ, अविवाहित स्त्री और अविवाहित पुरुष के विरुद्ध बरता जाने वाला जबरदस्त अन्तर मिट जायेगा। भविष्य में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2000 रुपये की व्यक्तिगत छूट और विवाहित व्यक्ति के लिए 1500 रुपये की अतिरिक्त छूट और अधिक से अधिक दो आश्रित-बच्चों के लिए, प्रत्येक आश्रित बच्चे पर 400 रुपये की छूट के अधीन, आमदनियों पर कर लगाया जायेगा। इस तरह जिस विवाहित के दो बच्चे होंगे उसे 4300 रुपये की आमदनी तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा, जबकि अभी यह सीमा 4000 रुपये है। व्यक्तिगत छूटों के आधार पर, नयी दर के हिसाब से, छूट की रकम वही 215 रुपये की पूर्ण राशि होगी जो सभी निर्धारितियों (एसेसीज) के लिए अधिकतम राशि होगी। इस सरलीकरण से 3.64 करोड़ रुपये की राजस्व-हानि होगी।

60. सरलीकरण के क्षेत्र में जो दूसरा परिवर्तन मैं करना चाहता हूँ उसका सम्बन्ध भविष्य निधि, बीमे के प्रीमियमों और बढ़नेवाली मियादी जमा योजना (क्यूमुलेटिव टाइम डिपाजिट स्कीम) के लिए किये जाने वाले अंशदानों से सम्बन्ध रखने वाली कमियों से है। इन मदों सम्बन्धी रियायतों की मुद्रा सीमा को व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये करने के अलावा अंशदान के रूप में रियायती मदों में धी गयी रकम की 50 प्रतिशत आमदनी में सीधी कमी करके रियायत देने का विचार है। मुझे विश्वास है कि इस व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति के लिये कर की देनदारी का हिसाब लगाने में सरलता हो जायेगी। असमर्थ आश्रितों की संस्थागत (इंस्टिट्यूशनल) देखरेख के सम्बन्ध में 2400 रुपये तक की आमदनी को करमुक्त रखने के लिए मैं एक नयी व्यवस्था भी जारी कर रहा हूँ। असंस्थागत (नॉन-इंस्टिट्यूशनल) देखरेख के सम्बन्ध में यह सीमा 600 रुपये होगी। माननीय सदस्य इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे कि सामाजिक कारणों से इस सम्बन्ध में कुछ राहत देना उचित है।

61. करों के ढांचे में सरलता लाते हुए और मौजूदा करों के स्थान पर एक संशोधित तथा एकीकृत अनुसूची जारी करते हुए मैंने व्यक्तिगत आमदनी के सभी स्तरों पर करों में कमी की है। नयी अनुसूची में, उन अर्जित (कमायी हुई) आमदनियों के लिए कर की उच्चतम सीमान्तिक (मार्जिनल) दर 65 प्रतिशत होगी जो 70,000 रुपये से अधिक होगी। इस के साथ ही अर्जित आमदनी के अधिभार (सरचार्ज) का भी पुनर्वर्गीकरण किया गया है और उस के अनुसार यह 1 और 2 लाख के बीच की आमदनी के लिए 5 प्रतिशत 2 और 3 लाख के बीच की आमदनी के लिए 10 प्रतिशत और 3 लाख से ऊपर की आमदनी के लिए 15 प्रतिशत रखा गया है। हमारी कर-निर्धारण योजना में, हम 15,000 रुपये की आमदनी को, विभिन्न उद्देश्यों से, विभाजन रेखा मानने लगे हैं। उदाहरण के लिए, वार्षिकी जमा योजना (एनुइटी डिपाजिट स्कीम) 15,000 रुपये तक की आमदनियों के लिए लागू नहीं होती। मैंने यह भी निश्चय किया है कि अनर्जित (बिना कमायी) आमदनी के कर-अधिभार के उद्देश्य से इस सीमा को उन्मुक्त सीमा (फ्री लिमिट) माना जाना चाहिए। अतएव इस प्रयोजन के लिए मौजूदा सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ा कर 15,000 रुपया कर देने का विचार है। इस व्यवस्था से और साथ ही सामान्यरूप से कर की दरों में कमी हो जाने से अनर्जित आमदनी के कर-अधिभार का आधार नीचा हो जाने से, अनर्जित आमदनियों पर लगने वाले अधिभार में वृद्धि करने की आवश्यकता जान पड़ती है। तदनुसार, 15,000 रुपये और 50,000 रुपये के बीच की अनर्जित आमदनियों पर 20 प्रतिशत की दर से और 50,000 रुपये से अधिक की ऐसी आमदनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कर-अधिभार लगाने का मेरा विचार है।

62. वित्त-विधेयक (फाइनेन्स-बिल) बहुत बड़ा दिखायी दे रहा है, क्योंकि इस में आयकर अधिनियम, 1961 के अनेक संशोधन किये गये हैं। मुख्यतः इसकी आवश्यकता, करों के ढांचे का सरलीकरण करने की इस योजना को क्रियात्मक रूप देने के लिए पड़ी है। लेकिन ये संशोधन स्थायी ढंग के हैं, इसलिए इन्हें आगे के वित्त-विधेयकों में दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

63. जैसा कि मैंने अभी ही बताया है प्रस्तावित परिवर्तनों से, व्यक्तिगत आय के सभी स्तरों पर, कर में कमी हो जायेगी। अनर्जित आय सम्बन्धी उच्चतम सीमान्तिक दर 88.125 प्रतिशत से घटकर 81.25 प्रतिशत और अर्जित आय सम्बन्धी दर 82.5 प्रतिशत से घटकर 74.75 प्रतिशत रह जायेगी, अर्थात् अर्जित आय पर 3 लाख रुपये से अधिक की आमदनी और अनर्जित आय पर 70,000 रुपये से अधिक की आमदनी पर सबसे ऊंची दर पर कर लगेगा। दो आश्रित बच्चों वाले विवाहित व्यक्ति के लिए 5,000 रुपये की अर्जित आय का कर 60 रुपये से घटकर 35 रुपये, 10,000 रुपये की अर्जित आय का 685 रुपये से घटकर 535 रुपये, 20,000 रुपये का 2,360

रुपये से घटकर 2,085 रुपये, 40,000 रुपये का 10,340 रुपये से घटकर 9,285 रुपये, 70,000 रुपये का 26,590 रुपये से घटकर 23,585 रुपये और 1 लाख रुपये का 44,615 रुपये से घटकर 39,160 रुपये रह जायगा। यह हिसाब, आपेक्षिक वार्षिकी जमा के कर सम्बन्धी लाभ को दृष्टि में रख कर लगाया गया है। इन कमियों के बावजूद हमारे कर की दरें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की आमदनी के तुल्य स्तरों की अपेक्षा ऊंची ही बैठेंगी। फिर भी, भारत में व्यक्तिगत करों के स्तर को घटाकर दूसरे देशों के स्तर के बराबर न लाने के लिए मैं खेद-प्रकाश नहीं कर रहा क्योंकि भारत और अमेरिका में आमदनी के समान स्तर का अर्थपूर्ण कल्याण का समान स्तर नहीं है। इस का अर्थ सम्पूर्ण समाज में समान आपेक्षिक स्थिति तो और भी नहीं है। भारत जैसे देश में एक या दो लाख की आमदनी ने आर्थिक शक्ति प्रकट होती है जो उस आर्थिक शक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसका उपभोग अधिक भाग्यशाली देशों में इसी आमदनी के लोग करते हैं।

64. कर की दरों में कमी और अधिभारों में परिवर्तन होने से पूरे वर्ष में राजस्व में 20.69 करोड़ रुपये की कमी होगी। 1965-66 में, करों के अग्रिम संग्रह के सम्बन्ध में सभी तरह के प्रत्यक्ष करों में 15 करोड़ रुपये की और भी कमी होगी। फिर भी मुझे पूरी आशा है कि जो परिवर्तन मैं ने किये हैं उन से आमदनी के निचले और दरमियानी समूहों के व्यक्तियों को कुछ राहत तो मिलेगी ही, साथ ही व्यक्तिगत बचतों के निवेश को बढ़ावा मिलेगा और करों की अदायगी से बचने का क्षेत्र और प्रलोभन कम हो जायगा।

65. जिन बड़े-बड़े परिवर्तनों का व्यौरा मैंने पहले दिया है उनके अलावा, आयकर के उपबन्धों में मैं कुछ अन्य परिवर्तन भी करना चाहता हूँ। नये औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सामान्य शीयरो में व्यक्तिगत रूप से पैसा लगाने वालों को कर-जमा-पत्र देने, भारत में आये और बैंकों में अनिवासी (नॉन-रेजिडेण्ट) खातों में जमा किये गये धन से हुई आमदनी के व्याज को कर-मुक्त रखने और सरकारी प्रतिभूतियों के व्याज को अनर्जित आय सम्बन्धी अधिभार से मुक्त रखने के अपने उद्देश्य की घोषणा मैंने 24 दिसम्बर, को की थी। इन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक में व्यवस्था कर दी गयी है। यह प्रस्ताव भी है कि दानों पर दी जाने वाली छूट उन रकमों के लिए भी दी जाय जो सार्वजनिक पूजा के स्वीकृत स्थानों के नवीकरण के लिए दी जायें और इस प्रकार के दानों को दानकर से मुक्त कर दिया जाय। प्रस्ताव है कि वार्षिक जमा योजना के सम्बन्ध में जो वार्षिकी प्राप्त हो सके उसे अर्जित आय माना जाय।

66. उन विदेशी तकनीशनों के लिए, जिन के ठेके सरकार द्वारा मंजूर किये गये हैं, कर की मौजूदा रियायत तीन साल के लिए है और जहाँ कर की अदायगी मालिक द्वारा की जाती है वहाँ साथ में दो वर्ष की अनुग्रह-अवधि (ग्रेस पीरियड) भी है। कुछ उद्योगों और कृत्रिम प्रक्रियाओं के लिए ऐसे तकनीशनों की सेवाओं को और भी ज्यादा अवधि के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रस्ताव है कि सरकार की अनुमति से दो वर्ष की दूसरी अवधि को तीन साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। बढ़ायी हुई अवधि में भी कर की अदायगी मालिक द्वारा, कर पर कर दिये बगैर का जा सकती है।

67. पेशेवर लोगों, जैसे कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वास्तुशिल्पी (आर्किटेक्ट) और सालीसिटरो के अभिवेदन (रेप्रेजेंटेशन) प्राप्त हुए हैं कि उन्हें भी करों में छूट दी जाय, ताकि वे किसी वार्षिक-निवृत्ति (सुपरएनुएशन) योजना के लिए कुछ व्यवस्था कर सकें। इस की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मैं उन फर्मों के साझेदारों को, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वास्तुशिल्पी, सालीसिटर और वकीलों का पेशा करते हैं, उन रकमों के सम्बन्ध में कर की राहत देना चाहता हूँ जो किसी स्वीकृत वार्षिकी योजना के अन्तर्गत जीवन वार्षिकियां खरीदने पर खर्च की जाय और यह खरीद बड़ी हुई उम्र में शुरू

की जाये। यह राहत उस रकम के लिए भी दी जायगी जो निवृत्ति-लाभ (रिटायरमेंट बेंनिफिट) की व्यवस्था करने वाली किसी स्वीकृत निधि में उनके द्वारा दी जायगी। यह राहत उन की कुल आमदनी में से ऐसी अदायगियों की सीधी कटौती के रूप में दी जायगी, लेकिन राहत की रकम कुल आमदनी के 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये में, जो भी कम हो, ज्यादा न होगी।

68. उन विदेशी निवेशकों द्वारा उनकी पूंजी के प्रत्यावर्तन को निरुत्साहित करने के लिए, जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे अपने शोधों को बेच डालते हैं, यह विचार किया गया है कि जब ऐसे व्यक्ति किसी से प्राप्त रकम को स्वीकृत औद्योगिक प्रतिभूतियों (सेक्यूरिटीज) में फिर से लगायें, तो मूल निवेश के लिए पूंजी लाभ कर की छूट उसी अनुपात में दी जाय जिस अनुपात में फिर से रकम लगायी जाय।

69. अनिवासी निर्धारितियों और उन निवासी निर्धारितियों पर, जो माधारणतः निवासी नहीं हैं, कर लगाने के आधारों में परिवर्तन किया जा रहा है। कुछ मौजूदा पेचीदगियों को दूर करने और करों के बोझ को कम करने के लिए इन निर्धारितियों पर 1965-66 के निर्धारण-वर्ष से उन दरों से भारत में उनकी निर्धारण योग्य आमदनी पर कर लगाया जायगा जो निवासियों पर लागू होती है। लेकिन अनिवासियों के मामले में व्यक्तिगत छूटों की रकम कम नहीं की जायगी। उन के मामले में दुनिया भर की आमदनी की हिसाब में लेने के विचार का परित्याग किया जा रहा है। इस मद में राजस्व-हानि अधिक नहीं होगी।

70. जहां तक मृत-सम्पत्ति-शुल्क और दान-कर का सम्बन्ध है, मौजूदा रियायतों में से कुछ को बढ़ाने का तथा कुछ ऐसे उपबन्धों में संशोधन करने का मेरा विचार है जिन की व्याख्या के कारण, मैं देखता हूं कि करदाताओं को व्यर्थ की परेशानी हो रही है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन-काल में कोई सम्पत्ति दान कर देता है तब कुछ अवस्थाओं में, अर्थात् यदि वह व्यक्ति उसे दान करने के बाद दो वर्ष के अन्दर मर जाये या यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले के दो वर्षों के दौरान वह सम्पत्ति उसके अधिकार में हो या वह उस सम्पत्ति का या उससे होने वाले किसी लाभ का भोग करे, तो, वह सम्पत्ति उस व्यक्ति के मरने पर उसकी जायदाद में शामिल की जा सकती है। दान-कर और मृत-सम्पत्ति-शुल्क की हमारी मौजूदा दरों का विचार करते हुए, इस स्थिति में सुधार करना आवश्यक है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि दो वर्षों की अवधि को घटा कर एक वर्ष कर दिया जाये और इसके अलावा यह व्यवस्था भी कर दी जाये कि यदि पत्नी, पुत्र या अन्य निकट सम्बन्धी को दिये गये सम्पत्ति के दान पर 1964-65 से लागू की गयी दान-कर की बढ़ायी गयी दरों के अनुसार दान-कर अदा कर दिया गया हो, तो वह सम्पत्ति दानकर्ता की जायदाद में सम्मिलित न की जाये, बशर्त कि उस की मृत्यु दान की तारीख से पांच वर्ष बाद हो। ऐसी व्यवस्था करने का भी मेरा प्रस्ताव है कि यदि दानकर्ता ऐसे मकान में रहे जो उसने अपनी पत्नी, अपने पुत्र या अपने अन्य निकट सम्बन्धी को दान कर दिया हो तथा दान पत्र के अनुसार या किसी समपाष्विक व्ययन (कोलैटरल डिस्पोजिशन) के अनुसार उसके लिए निवास या किसी लाभ का अधिकार रक्षित न किया गया हो, तो वह सम्पत्ति उसकी जायदाद में शामिल न की जाये, बशर्त कि दानकर्ता की मृत्यु दान की तारीख से एक वर्ष बाद हो। फिर, जब किसी मृत कर्मचारी के परिवार को सरकार द्वारा या किसी अन्य निकाय द्वारा या नियोजक द्वारा स्थापित और आयकर अधिनियम के अधीन स्वीकृत वार्धक्य-निधि (सुपरएनुएशन फण्ड) से या किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा रक्षित इसी प्रकार की निधि से पेंशन दी जाती है तब पेंशन के पूंजी-कृत मुख्य पर मृत-सम्पत्ति-शुल्क लगता है। यह आवश्यक समझा जाता है कि ऐसे मामलों में होने वाला कष्ट ऐसी पेंशन को मृत-सम्पत्ति-शुल्क से मुक्त कर के रद्द किया जाये। इन व्यवस्थाओं के कारण होने

वाली राजस्व-हानि नाममात्र होगी। इसके अलावा, ऐसी व्यवस्था करने का भी मेरा प्रस्ताव है कि किसी वान-पत्र पर दिये गये मुद्रांक शुल्क (स्टैम्प ड्यूटी) की छूट दान-कर में की जाने वाली कटौती के रूप में, कुछ सीमाओं के अन्दर और कुछ शर्तों के अनुसार, दी जाये।

71. अब मैं बेहिसाबी (अनएकाउण्टेड) आय और सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों की चर्चा करता हूँ। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, ग्रन्थव्यवस्था में इनके कारण बहुत खराबी पैदा होती है। इस दोष को दूर करने की समस्या बहुत जटिल है। जोरों से तलाशी लेने आदि की व्यवस्था के अलावा हमने ऐच्छिक उद्घाटन (वोलंटरी डिस्क्लोजर) प्रोत्साहित करने के लिए पहले ही कई व्यवस्थाएँ की हैं। इस प्रकार स्वेच्छा से बतायी गयी रकमों को दण्ड से मुक्त किया जा रहा है। ये उपाय उद्घाटनों को प्रोत्साहित करने में कुछ सफल हुए हैं, विशेषकर ऐसे लोगों द्वारा किये जाने वाले उद्घाटनों को जिन्हें अपेक्षाकृत छोटी और वरमियानी आमदनियाँ बतानी हैं। बड़े पैमाने पर उद्घाटन करने को प्रोत्साहन देने के लिए और ऐसे लोगों को अवसर देने के लिए, जो अनुचित परेशानी से बचकर इस प्रकार के उद्घाटन करके अपने आप में सुधार करना चाहते हैं, समय समय पर विभिन्न सुझाव दिये गये हैं। मुझे पूरी आशा है कि कर की दरों में कमी करने का मैंने जो प्रस्ताव किया है उससे भविष्य में कर से बचने की गुंजाइश और प्रलोभन कम हो जायेगा। इस प्रकार जिन लोगों ने पहले कर अपवचन किया है उन्हें प्रकट होकर अपना दोष स्वीकार करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। मैं यह बात मानता हूँ कि ऐसा हल दृढ़ निकालना आसान नहीं है जो उन लोगों के प्रति भी न्यायपूर्ण हो जिन्होंने ईमानदारी से अब तक कर अदा किये हैं और साथ ही इतना युक्तियुक्त भी हो कि जो लोग अपने पहले के कर-अपवचन से उद्धृष्ट होना चाहते हैं उन्हें स्वेच्छा से पर्याप्त परिमाण में उद्घाटन करने के लिए प्रोत्साहन मिले। बेहिसाबी आमदनी और सम्पत्ति के मूल्य में जो विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विचार पाये जाते हैं उनका विचार करते हुए मैंने समस्या का हल ढूँढने का प्रयत्न किया है। मैं केवल यह आशा कर सकता हूँ कि जो कुछ करने का मेरा विचार है उससे ईमानदार करदाता को कष्ट नहीं होगा और जो लोग अतीत में पथभ्रष्ट हो गये थे उन्हें नागरिक उत्तरदायित्व के मार्ग पर वापस आ जाने का औचित्य दिखाई देगा।

72. संक्षेप में मेरा प्रस्ताव यह है। जिन व्यक्तियों के पास बताने के लिए छिपी हुई आमदनी है वे प्रासंगिक विवरण के साथ इसे प्रकट कर सकते हैं और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक में बिना बतायी आमदनी का 60 प्रतिशत नकदी के रूप में जमा कर सकते हैं। इस प्रकार बतायी हुई आमदनी का 40 प्रतिशत आयकर अधिकारियों को सूचना देकर निर्धारितियों के खातों में दिखलाया जा सकता है। इस तरह बतायी गयी आमदनी के सम्बन्ध में कर-निर्धारण का कोई और प्रश्न नहीं उठेगा और उनका नाम पता आदि प्रकट नहीं किया जायेगा। यह सुविधा अब से तीन महीने के लिए ही, मई के अन्त तक के लिए, उपलब्ध होगी। लोगों को शीघ्रता से अपनी रकमें बताने को प्रोत्साहित करने के लिए बतायी हुई सभी रकमों के कर और उन पर मार्च महीने में दिये हुए कर की 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में, कर की प्रभावी दर 5 प्रतिशत होगी। जो लोग यह समझते हैं कि बतायी जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में जिनकी कर-सम्बन्धी वेनदारी 57 या 60 प्रतिशत से कम होगी उन्हें सामान्य ढंग से अपनी रकम बताने की और इस तरह बतायी रकम पर, आयकर अधिकारियों द्वारा समुचित निर्धारण के बाद उचित दरों पर कर लगवाने की स्वतंत्रता रहेगी। जिस योजना की रूपरेखा मैंने अभी ही बतायी है उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए वित्त-विधायक में उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हम तलाशियाँ जारी रखना चाहते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि जो लोग अपनी इच्छा से छिपायी रकमें बताने के इस खास अवसर की उपेक्षा करेंगे उनके साथ पेश आने के लिए वह सभी वैध उपायों से काम लें।

73. साथ ही, एक बार फिर स्वण बाण्ड जारी करने का मेरा प्रस्ताव है। पिछली बार जब हमने ऐसा बाण्ड जारी किया था तो उसका स्वागत हमारी आशा के अनुरूप नहीं हुआ था। एक बात को छोड़ कर, नये बाण्ड बिलकुल पुराने बाण्डों की शर्तों पर जारी किये जायेंगे। पिछले बाण्डों के जारी होने के बाद ब्याज की दरों में हुई वृद्धि को देखते हुए नये बाण्डों के ब्याज की दर 7 प्रतिशत वार्षिक होगी। जिन्होंने पहले क्रमों के स्वण बाण्ड खरीदे थे और राष्ट्रीय संकट के समय सरकार के साथ सहयोग किया था उन्हें भी उनके बाण्डों के चलन के बाकी वर्षों में ब्याज की इसी ऊँची दर का लाभ उठाने दिया जायेगा। जो भी पुराना बांड रिजर्व बैंक में पेश किया जायेगा और उस पर बैंक का सम्मोदन (इम्प्रिमाटर) होगा उस पर पहले अप्रैल 1965 के बाद नयी दर से ब्याज मिलेगा। यहां इतना और बताना चाहूंगा कि इस रियायत को ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि यह ऐसे सभी मामलों में साधारण रूप से दी जायेगी। मैं ऐसे हर व्यक्ति से, जिसके पास बताया या बगैर बताया हुआ सोना है, अपील करूंगा कि वह नये बाण्डों को अधिक से अधिक संख्या में खरीदे। नये स्वर्ण बाण्ड तीन महीने के लिए अर्थात् मई के अन्त तक बाजार में बिकेंगे।

सारांश

74. जिन परिवर्तनों के लिए मैंने प्रस्ताव किये हैं उनके सम्पूर्ण प्रभाव का अब मैं सारांश बताता हूँ। कर की वर्तमान दरों के आधार पर, 10 करोड़ रुपये की कुल बचत में, अप्रत्यक्ष करों के परिवर्तनों से 1.5 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। दैनिक उपभोग की बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन शुल्कों में कमी हो जाने से 29.5 करोड़ रुपये की जो राजस्व-हानि होगी वह सिगरेटों और टायरों सम्बन्धी प्राविधिक परिवर्तन से प्राप्त होने वाले 75 लाख रुपये के राजस्व, तांबे, इस्पात की चीजों और टीन की चद्दरों आदि के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से 15.75 करोड़ रुपये की प्राप्ति और सीमा शुल्कों में 14.5 करोड़ रुपये की वृद्धि से बराबर हो जायेगी।

75. जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, व्यक्तिगत छूटें देने से 3.64 करोड़ रुपये की और दरों में परिवर्तन करने से 20 करोड़ रुपये की राजस्व-हानि होगी। जिससे सम्पूर्ण हानि का जोड़ 23.64 करोड़ हो जायेगा। अर्जित और अनर्जित अधिभारों में हेरफेर होने से 69 लाख रुपये की राजस्व-हानि होगी। धारा 104 की कम्पनियों को रियायतें देने से राजकोष की 2.73 करोड़ रुपये की हानि होगी। अन्य विविध रियायतों से होने वाली हानि 2.73 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 1965-66 में 15 करोड़ रुपये की और हानि होगी और वह इस कारण कि इस वर्ष की सभी नयी दरें इस वर्ष की कर योग्य आमदनी और उस आमदनी के सम्बन्ध में भी लागू होगी जिस पर कर अग्रिम रूप से दिया जा सकता है। शहरी सम्पत्ति पर लगने वाले सम्पत्ति कर से 1.5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस तरह, प्रत्यक्ष करों के सभी परिवर्तनों से, जिनमें निगम करों के परिवर्तन भी शामिल हैं, 1965-66 में कुल 42.90 करोड़ रुपये की राजस्व-हानि होगी।

76. अनुमान है कि प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत, सभी साधनों से 704.05 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। इसमें से 42.90 करोड़ रुपये को, उपयुक्त रियायतों के कारण, हानि के रूप में कम करना पड़ेगा। फिर भी, व्यक्तिगत करों में स्पष्ट कमी और कर-संग्रह में सुधार की दृष्टि से मैं 30 करोड़ रुपये जमा कर रहा हूँ जिससे प्रत्यक्ष करों के सभी स्रोतों से कुल 691.15 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है। इस दृष्टि से, बजट की रकम के मुकाबले, प्रत्यक्ष करों में 12.90 करोड़ रुपये की कमी रहेगी। इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष करों

में 1.5 करोड़ रुपये का अधिशेष है। इसे और उत्पादन शुल्कों में से राज्यों के हिस्से के परिणाम को हिसाब में लेते हुए राजस्व में 6.38 करोड़ रुपये का हानि होगा, जिसने करो के वर्तमान स्तरों के आधार पर होने वाले सम्पूर्ण अधिशेष को मिला कर, 3.72 करोड़ रुपये का वास्तविक अधिशेष रहेगा।

77. ऐच्छिक उद्घाटन योजना (वोलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम) से होने वाली प्राप्तियों के सम्बन्ध में मैंने कोई रकम जमा नहीं की है। वास्तव में मुझे आशा है कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी हानि, न केवल साल भर में पूरी हो जायेगी, बल्कि कुछ अधिक की ही प्राप्ति होगी जिसका कारण किये गये परिवर्तनों के परिणामस्वरूप न केवल करों के संग्रह में सुधार होना है बल्कि ऐच्छिक उद्घाटन योजना के अन्तर्गत भी प्राप्ति होना है। इसलिए आशा की जा सकती है कि अगले वर्ष का अधिशेष और भी अधिक होगा। इसी बात की ध्यान में रखते हुए मैंने प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में से राज्यों के हिस्से की रकम में किसी कमी का अनुमान नहीं किया है। दूसरी ओर, आयकर सम्बन्धी राजस्व में राज्यों के हिस्से में जो वृद्धि होगी उससे, मेरी दृष्टि में, उत्पादन-शुल्कों की प्राप्तियों में से राज्यों के हिस्से में होने वाली कमी न केवल पूरी हो जायेगी बल्कि उन्हें कुछ अधिक रकम की प्राप्ति होगी।

78. मेरे लिए यह कुछ सन्तोष का विषय है कि मैं ऐसा बजट प्रस्तुत करने में समर्थ हूँ, जिसमें राजस्व और पूंजी दोनों खातों की दृष्टि से, यदि अधिशेष रहने की नहीं, ० सन्तुलन रहने की पूरी सम्भावना है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों को भी इस बात से ऐसा ही सन्तोष प्राप्त होगा कि आयोजना की आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था करत हुए और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में कुछ राहत देने हुए हम एक सन्तुलित बजट पेश करने में समर्थ हो सके हैं। अन्त में मैं माननीय सदस्यों से और हमारी कर-प्रणाली से प्रभावित सभी व्यक्तियों से अपील करूंगा कि वे प्रस्तुत बजट को इस देश के करों के ढांचे को एक सुदृढ़ और व्यवस्थित आधार पर लाने की हमारी हार्दिक इच्छा का प्रतीक मानें।

अंतिम अनुमानों का सारांश

प्राप्तियां	विवरण—क		(लाख रुपयों में)
	राजस्व बजट		
	बजट	संशोधित	बजट
	1964-65	1964-65	1965-66
सीमा शुल्क . . .	3,36,37	3,85,00	4,05,00 + 14,50* }
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क . . .	7,69,54	7,73,05	8,27,17 - 7,98* }
निगम कर . . .	2,96,67	3,42,00	3,86,00 - 14,40* }
आय सम्बन्धी कर . . .	2,47,28	2,68,00	2,94,00
मृत सम्पत्ति शुल्क . . .	7,40	7,00	7,40
सम्पत्ति कर . . .	10,20	11,05	12,00 + 1,50* }
व्यय कर . . .	1,55	75	1,55
दान कर . . .	3,10	3,10	3,10
अन्य शीर्षक . . .	21,57	21,93	23,87
ऋण व्यवस्था . . .	2,52,14	2,65,57	2,96,73
प्रशासनिक सेवाएं . . .	8,98	9,13	9,51
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं . . .	28,13	30,40	23,57
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं आदि . . .	11	12	13
सरकारी निर्माण कार्य आदि . . .	3,75	3,90	3,94
परिवहन और संचार . . .	6,81	7,41	6,75
मुद्रा और टकसाल . . .	53,73	52,11	61,69
विविध . . .	17,29	21,38	25,47
अंशदान और विविध समायोजन . . .	31,08	32,71	34,81
असाधारण मदें . . .	1,43,31	1,24,62	60,50
षट्पाइये—आयकर में से राज्यों को दिया जाने वाला अंश . . .	-1,07,49	-1,23,77	-1,22,93
षट्पाइये—मृत सम्पत्ति शुल्क में से राज्यों को दिया जाने वाला अंश . . .	-7,22	-6,78	-7,17
जोड़ . . .	21,24,30	22,28,41	23,53,09 - 6,38* }

अंतिम अनुमानों का सारांश

विवरण क

राजस्व बजट

(लाख रुपयों में)

व्यय	बजट	संशोधन	बजट
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह .	25,34	26,41	28,88
ऋण-व्यवस्था . . .	3,18,41	3,17,61	3,56,11
प्रशासनिक सेवाएं . . .	81,84	82,17	91,36
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं . . .	1,68,14	1,65,11	1,84,66
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं आदि .	1,84	1,33	1,98
सरकारी निर्माण कार्य आदि .	20,21	20,66	22,98
परिवहन और संचार . . .	10,18	10,37	10,62
मुद्रा और टकसाल . . .	17,33	15,36	16,40
विविध	98,51	95,17	1,16,27
अनुदान और विविध समायोजन—			
राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान	2,89,08	2,88,56	3,27,11
केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों का हिस्सा .	1,40,98	1,27,34	1,40,84
अन्य व्यय	4,13	4,32	4,69
असाधारण मदें	1,47,52	1,28,04	65,84
रक्षा-सेवाएं (वास्तविक) .	7,17,80	7,16,81	7,48,74
जोड़	20,41,31	19,99,26	21,16,48
कमी (—)			
अधिशेष (+)	(+) 82,99	(+) 2,29,15	(+) 2,36,61 } -6,38*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

अंतिम अनुमानों का सारांश

विवरण ख

पूँजी बजट

(लाख रुपयों में)

	बजट 1964-65	संशोधन 1964-65	बजट 1965-66
प्राप्तियां			
राजस्व अधिगण	82,99	2,29,15	2,36,61
			-6,38*
सरकारी ऋण :			
भारत में लिया जाने वाला	3,00,00	2,97,70	2,70,00
विदेशों में लिया जाने वाला	6,96,97	6,53,92	6,68,86
ऋणों और अप्रियों का परिशोध :			
राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र	2,38,92	2,31,31	2,73,69
अन्य	46,03	70,00	60,00
छोटी बचतें (वास्तविक)	1,25,00	1,35,00	1,35,00
भविष्य निधियां (वास्तविक)	54,29	49,62	54,66
आयकर वार्षिकी जमा (वास्तविक)	67,00	65,00	65,00
पी० एल० 480 सम्बन्धी जमा रकमें (वास्तविक)	-84,84	11,00	1,91,00
रेल तथा डाक तार निधियां (वास्तविक)	43,12	17,81	48,23
विशेष विकास निधि (वास्तविक)	2,97,65	2,75,50	1,43,16
अन्य ऋण, जमा आदि (वास्तविक)	1,25,86	51,69	37,74
जोड़	19,92,99	20,87,70	21,83,95
			-6,38*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

अनिम अनुमानों का सारांश

विवरण ख

पूज बजट

(लाख रुपयों में)

व्यय	बजट	मशोधन	वज ट
राजस्व की कमी
पूँजीगत व्यय :			
असैनिक	3,86,01	3,42,96	3,59,73
रक्षा	1,36,10	1,17,95	1,30,05
रेलें	2,53,00	2,51,92	2,40,00
डाक और तार	20,59	26,59	32,83
ऋण का परिशोध :			
भारत में लिये जाने वाले	1,92,00	1,91,54	1,70,00
विदेशों में लिये जाने वाले	67,26	85,11	97,29
ऋण और अग्रिम :			
राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र	6,21,71	7,07,92	7,12,07
अन्य	2,38,22	2,71,01	3,51,82
जोड़	19,14,89	19,95,00	20,93,79
जोड़िये—विशेष विकास निधि में			
ऋण सहायता का काल्पनिक			
अन्तरण	1,74,78	1,73,00	80,00
जोड़—व्यय !	20,89,67	21,68,00	21,73,79
सम्पूर्ण कमी (—)			
अधिशेष (+)	-96,68	-80,30	+ 10,16 -6,38*
जिसकी पूर्ति			
(i) राजकोष दुण्डियों को			
बढ़ाकर (+) घटाकर (—)	+ 96,00	+ 72,00	-10,00 + 7,00*
(ii) नकदी रकम में से निकासी			
करके	+ 68	8,30	-16 -62*
की जानी है ।			
जोड़	96,68	80,30	-10,16 + 6,38*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

Budget 1965-66

Finance Minister's Speech

New Delhi, the 27th February 1965

Sir.

I rise to present the Budget of the Government of India for the year 1965-66. On this, the first occasion in independent India, when our beloved leader, Jawaharlal Nehru, is absent from these proceedings, may I say that I miss him, as I am sure we all do. Honourable Members would permit me, therefore, to begin by paying my humble tribute to his sacred memory. For seventeen long years after Independence, Jawaharlal Nehru dominated the Indian scene, giving meaning and substance to our aspirations as a nation. No aspect of our life, be it related to unity in the country, or economic planning for a better future, or the maintenance of peace and goodwill among nations, escaped the mark of his unmistakable genius. Even such mundane matters as the Budget and economic policy were raised to a lofty plane, where they became instruments for advance towards a shining vision of economic independence, of prosperity with social justice. It is now left to us, to my leader the Prime Minister, to his colleagues in the Cabinet, as, indeed, to Honourable Members and to everyone else in the country, to carry forward the legacy of Jawaharlal Nehru according to our lights. And I can only hope that the Budget I am about to present will help to fulfil this obligation in some small measure.

2. This year's Budget has a unique significance in many ways. As the last budget of the current Plan period, it marks the climax of our efforts for the fulfilment of the Third Plan. It represents, at the same time, the setting of the stage for the more complex and sophisticated and, indeed, difficult tasks which await us in the coming Plan period. Honourable Members are by now already familiar with our preliminary thinking on the Fourth Plan. Apart from serving the ends of our plans for development, budgetary policy must also make an impact on the immediate problems that confront us from year to year. On particular aspects of the economic situation which have caused us anxiety during the past year such as the rising prices, the difficulties in raising adequate resources for investment and the sharp decline in our foreign exchange reserves, I have made statements in the House from time to time. Like last year, the Economic Survey has also been published a few days in advance of the Budget. My task today is to that extent lightened. I shall, therefore, proceed to outline straight-away the budgetary outcome for the current year as now estimated.

3. The Budget forecast an overall uncovered gap of Rs. 97 crores. It now looks as if the deficit will be somewhat smaller at about Rs. 80 crores. This has been possible in spite of sizable increases in expenditure in certain directions, both revenue and capital. This, relief and rehabilitation of refugees has claimed Rs. 12 crores more. Increases of dearness allowance have raised expenditure this year by Rs. 38 crores. On the capital side, apart from larger provision for the purchase of fertilizers and for the Food Corporation of India, there has been a sizable increase of Rs. 85 crores in loans to State Governments due mainly to larger ways and means advances, and increased Central assistance for Plan schemes, particularly for agriculture, irrigation and power. These additional outlays have been offset by reductions in expenditure under other items and by improvement in revenue collections. The reduction in the capital outlay of the Centre relates mainly to the steel plants, defence and net outlay on food purchases. Details of variations in expenditure are given as usual in the Explanatory Memorandum.

4. Revenue collections are expected to show an improvement of Rs. 49 crores under Customs and Rs. 66 crores under Income and Corporation Taxes. Excise receipts are expected to be about the same as budgeted. Together with a reduction in revenue expenditure of Rs. 42 crores spread over many heads, the revenue surplus is now expected to be Rs. 229 crores as against the Budget Estimate of Rs. 83 crores.

5. Under capital receipts, collections under small savings have been encouraging this year and are now estimated at Rs. 135 crores as against the Budget Estimate of Rs. 125 crores. The Railway funds deposited with Government, however, show a decline in relation to Budget Estimate and receipts from foreign loans are likely to be lower by Rs. 43 crores.

6. Honourable Members will see that despite substantial additional requirements for various purposes I have just referred to, such as increase in dearness allowance, refugee rehabilitation and assistance to the States, the overall deficit for the current year will be somewhat less than originally forecast. In part, this reflects the success of our efforts to bring about economies in expenditure after the presentation of the last Budget. In an otherwise difficult situation, the reduction in the overall deficit calls for some satisfaction. But with the continuance of inflationary pressures in the economy, the need for restraint on wasteful or avoidable expenditure and for efforts to get the maximum benefit from outlays already incurred remains as great as ever. Only so can we reconcile our desire for rapid economic growth and the imperative requirements of financial stability, both internal and external.

7. Honourable Members will have noticed also that the revenue surplus this year will be even larger than last year. It is, however, the overall position, taking the revenue and capital account together, which is really relevant for the health and stability of the economy as a whole. In a growing economy, with progressive increase in Plan outlays, the balancing of the capital budget cannot be done entirely by mobilisation of voluntary savings and external assistance. These have to be supplemented increasingly by public savings realised through a revenue surplus. The achievement of a sizable revenue surplus this year is, therefore, a step in the right direction.

8. Turning to developments in the economy, agricultural production recovered somewhat during the 1963-64 season from the low level in the preceding year. During the current year, there is every likelihood of total production of food-grains and commercial crops showing a further and substantial increase. Under normal circumstances, the improvement in agricultural production should have led to a decline in prices from the high levels already reached. The prevalence of inflationary pressures at different levels in the economy and speculative withholding of supplies have, however, prevented prices from falling to the extent that they should have. The fiscal and monetary measures which we have taken and are now taking will, I hope, bring about a fall in prices to the extent economically justified. We shall, however, take care that the agencies we have created for the purchase of foodgrains will maintain prices at levels remunerative to the farmer, so that he will have a continuing incentive for producing more. These agencies will at the same time take advantage of the current improvement in supplies to build up buffer stocks so that, in future, we shall be able to deal better with any fluctuations in agricultural output.

9. Industrial production has been rising at the rate of 8 to 9 per cent per annum for the last two years. During the first half of the current year, there were some signs of a slackening in the pace of production. But industrial production is expected to recover during the second half of the current fiscal year and the increase in production for the year as a whole should be of the order of 8 per cent. Taken together with the improvement in agricultural production, the growth rate of the economy in 1964-65 should be higher than in 1963-64 when national income in real terms is estimated to have increased by about 4½ per cent.

10. In a number of important industries such as steel, cement, aluminium, cotton-spinning, etc., further increases in production would depend on the establishment of new capacity. Programmes of expansion in the public sector in steel, machine-building, fertilizer production, etc., are making progress, and these should result in improvement in supplies over the next two or three years. Indian industry has now reached a stage, when it can, and must, branch out into new and complex lines of development. The expansion of capacity we need now, both in the public and the private sector, has to take place not only in established industries but even more so in new activities where requirements of capital and technical know-how are heavy. We have taken several measures to encourage greater ploughing back of profits for investment as well as to provide greater loan finance to private industry. It is equally important to encourage a larger flow of individual savings so as to promote a greater participation by individual citizens in the growth of industry. The new financial institutions that we have created can assist in this process, by dissemination of information and otherwise enable individuals to judge better the kind of industry that they should invest in. But

the primary objective must be to raise the capacity for individual savings and to improve the performance of industry so that it is able to earn and offer an attractive return on the capital invested.

11. Efficiency in the running of enterprises, whether public or private, depends to a great extent on appropriate pricing policies. On the one hand, prices paid by industry for scarce resources and materials it uses should reflect their true scarcity. At the same time, the prices charged by enterprises for their products should provide sufficient resources to industry for expansion without exploitation of the consumer. We are attempting to evolve a price structure for agricultural commodities in keeping with these general principles. In regard to industrial products also, we have endeavoured to raise the cost of capital and of imports in keeping with the scarcity of savings and foreign exchange in the economy, while permitting increases in the prices of final products wherever necessary. Despite continuing difficulties in regard to raw materials and the general upward pressure on prices the policy of decontrol initiated in 1963 has been carried forward, particularly in respect of steel products. We have also raised the prices to the extent necessary of a number of basic commodities, such as coal, from time to time.

12. Improvement in productive efficiency and appropriate pricing policies are as much important for public sector enterprises as they are for private industry. In my last Budget Speech I had drawn attention to the importance of a careful choice of projects, after a detailed examination of costs and benefits. Careful selection of projects, quick implementation, efficient working, appropriate pricing policies and adequate returns on investments are all integral parts of the process of ensuring rapid growth. It is in this sense that we have to devote increasing attention to planning in depth. Maximising the fruits of past investment offers the best scope for further advance. Consolidation and expansion, a firm foot on the ground and sights set high, are not thus conflicting but complementary objectives.

13. In the field of money and credit, it is a matter of some satisfaction that the pace of monetary expansion which was very rapid in 1963-64 has slackened somewhat during the current year. Expansion of bank credit to Government has been somewhat less this year. I would like to draw the attention of Honourable Members to the fact that over the past few years, a part of the market loans floated by Government has had to be subscribed by the Reserve Bank. To this extent, a part of our long-term borrowing represents deficit financing rather than mobilisation of the voluntary savings of the people. This form of deficit financing must also be necessarily reduced, and indeed eliminated, if we are to make a decisive impact on the forces of inflation in the economy. For this reason, our borrowing programmes in future, both at the Centre and the States, will have to be based on a strictly realistic assessment of the flow of genuine savings. Greater efforts must be made at the same time to mobilise larger amounts from the people by way of small savings and subscription to market securities. Honourable Members are aware that we have taken steps to increase interest rates in the economy to a significant extent over the past year. I propose to introduce a new series of Small Savings Certificates with a higher rate of interest than at present. Interest on the new certificates will be taxable, unlike in the case of existing instruments, which also will be continued. The availability of yet another instrument at a higher, though taxable, rate of return will, I am sure, provide a greater inducement for saving to people of small and medium income, whose tax liability is also of a small or medium order.

14. The expansion of bank credit to the private sector during the current busy season has been somewhat smaller than in the corresponding months of the preceding busy season. The current busy season, however, has several weeks to go yet. It is my expectation that the measures that the Reserve Bank announced ten days ago will act as a brake on the expansion of bank credit during the coming weeks. The contraction in bank credit during the slack season this year will also have to be large enough to ensure that the total increase in credit over the year is just sufficient to meet the requirements of growing production. Monetary expansion during the Third Plan period so far has kept ahead of the growth in real production. This situation cannot be allowed to continue any further. In future, expansion of bank credit both to the public and the private sector will have to be so limited that the increase in money supply is no more than what is warranted by realistic expectations regarding the growth of output.

15. The State Governments also have an important role to play in strengthening fiscal and monetary discipline in the country. Some of the State Budgets for

the coming year which have been presented so far reveal deficits. I propose to have discussions with State Governments to make sure that their operations are generally in line with our policy of curbing inflationary pressures in the economy.

16. Honourable Members are aware that proper monetary management in the country has been rendered difficult for some time by the existence of unaccounted income and wealth in the country. This unaccounted income and wealth, which is derived mainly from tax evasion and from violations of price control measures, has been responsible to a considerable extent for speculative activity and for bidding up the prices of goods and property in general. Apart from the measures we have already taken including searches, stricter enforcement and more severe penalties, I propose to take some additional measures to mitigate substantially the mischief of unaccounted incomes and wealth already in existence and to reduce the scope and incentive for their accumulation over the years to come. I propose also to take some measures to discourage excessive investment in urban property, which comes in the way of adequate resources being available for more productive purposes.

17. In my statement to the House on February 17, I had dwelt at some length on our extremely difficult foreign exchange position. I do not wish to repeat what I had already said on that occasion. I would only underline the fact that our foreign exchange reserves have been depleted to such an extent that we are unable at present to withstand any small pressure on these reserves, without running into a critical situation. Some strengthening of our foreign exchange reserves is, therefore, a matter of vital importance. We have made considerable progress in reducing our reliance on imports in a number of fields. Our export promotion during recent years is also a matter of some satisfaction. Even so, given the necessity to strengthen the reserves and to meet the requirements of imports in a growing economy, the need for vigorous export promotion remains as great as ever.

18. We have been receiving sizable assistance from friendly foreign governments and international institutions. Honourable Members will, I am sure, join me in expressing once again our gratitude to our friends abroad for giving us a helping hand. The Aid-India Consortium organised by the World Bank pledged a further sum of \$1028 million last year in support of the Third Five Year Plan. A significant portion of this assistance is not tied to specific projects but is intended for import of materials, components and spares in general. This kind of assistance is of special importance to us in the context of current balance of payments difficulties and I have every hope that Consortium assistance during the coming year will include even larger sums for purposes which give immediate relief to the balance of payments. Outside the Consortium, we have received generous assistance from the United States for the import of foodgrains and other agricultural commodities under the PL 480 programme. Countries which are not members of the Consortium have also provided additional assistance in 1964. More recently, we have concluded an agreement with the U.S.S.R. for the Bokaro Steel Plant. I should not fail to mention also the gift of 150,000 tons of wheat from Australia which was announced only a few days ago. This generous and timely gesture is a matter of particular satisfaction to me as, I am sure, it augurs well for increasing cooperation between our two Commonwealth countries.

19. Considerable progress has been made in the utilisation of external assistance, which has now reached a rate when it practically equals the commitment of new assistance. Even so, a part of the assistance committed during the current Plan period will necessarily be carried over into the Fourth Plan. We are currently reviewing our foreign exchange requirements during the Fourth Plan period and we hope, during the coming year itself, to initiate discussions with friendly foreign governments and institutions to secure advance commitment for our requirements, to the maximum extent possible. It is only on the basis of such advance planning for foreign aid that we can be confident of beginning the Fourth Plan without any hiatus in the process of growth.

20. In some measure, we have also been endeavouring to assist other developing countries. Our aid to Nepal next year, for example, is estimated to be Rs. 8.5 crores. Assistance for Sikkim and Bhutan will be of the order of Rs. 6.2 crores. We have endeavoured also to facilitate joint ventures in a number of African countries for the establishment of industries such as sugar, cotton, textiles, cement and vegetable oil. During the next year, we propose to provide Rs. 48 lakhs for technical assistance to countries in South and South-East Asia and Africa and Rs. 1.43 crores by way of contribution to the United Nations expanded Programme of Technical Assistance and the United Nations Special Projects Fund.

21. There has been a great deal of discussion in India in recent months about the role of private foreign investment in our plans for development. We have recognised for a long time that private foreign investment has a role to play not only as an essential supplement to assistance from friendly foreign governments and international institutions but also as a catalyst for the development of technical skills and enterprise among our own people. For this reason, we have encouraged private foreign investment in association both with the public and the private sector. All the incentives and facilities that we have given to Indian enterprise for promoting investment are available equally to private foreign enterprise; and we give every facility for repatriation of profits to foreign investors. This policy of hospitable and fair treatment will be continued in future; and our general policies, whether in regard to taxation, industrial licensing or price controls, must be consistent with our desire to harness every possible source of dynamism and enterprise, whether domestic or foreign, public or private, to the task of rapid economic growth.

22. The Fourth Five Year Plan will involve large investments in the public and the private sector. The first and foremost precondition for mobilisation of resources for financing these investments is the maintenance of an environment of financial and monetary stability. It is only then that voluntary savings could be encouraged and directed to productive uses. Equally important is a degree of stability in our taxation policies. It may be necessary to adjust the rates of indirect taxation from year to year in keeping with supply and demand conditions. But a greater degree of stability in regard to the structure of direct taxation is of vital importance as it has a bearing on long-term decisions in regard to savings and investment. My budget proposals this year have been designed to serve this end at least in part. I for one do not consider that the scope for additional resource mobilisation is already exhausted. But there is no reason why whatever framework we need for raising resources for the Fourth Plan should not be erected in all its essentials before we embark on the implementation of the Plan.

23. In the ultimate analysis, the resources available to the public sector and to the private sector, the resources available by taxation, by mobilisation of savings or by realisation of adequate profits, are all part of the same pool. We cannot hope to tap one particular source without affecting other sources or divert more to one particular channel without affecting what is left for other purposes. More production and restraint on consumption, avoidance of waste and efficient use of scarce resources, are the only ultimate instruments for promoting higher savings and investment. Budgetary policy, therefore, is not simply or even primarily a matter of balancing receipts and expenditures. It is no doubt of paramount importance to keep deficit financing within safe limits and, indeed, to avoid it altogether. But the level at which the budget is balanced and the manner in which this balance is secured are even more relevant to the flow of savings and investments and to the performance of the economy as a whole.

24. The budget estimates for the next year to which I shall now turn have been framed with these considerations in mind. The expenditure on revenue account is estimated at Rs. 2,116 crores, which is Rs. 117 crores more than the revised estimate for the current year. At existing rates of taxation, including the 10 per cent surcharge on imports I announced ten days ago, the total revenue is expected to be Rs. 2,353 crores. The revenue surplus will, therefore, be Rs. 237 crores, i.e. Rs. 8 crores more than in the current year.

25. Of the total revenue expenditure of Rs. 2,116 crores next year, Rs. 749 crores will be for Defence Services. This is Rs. 32 crores more than in the current year. But actual rupee expenditure will not increase quite so much because purchases of stores and aircraft, the full value of which is included in the expenditure estimate are being made on deferred payment terms. Expenditure under civil heads is estimated at Rs. 1,367 crores, which is Rs. 85 crores more than in the current year. If the amounts transferred to the Special Development Fund in respect of PL 480 grants are disregarded, the actual increase in civil heads would, in fact, be greater. The major part of the increase is explained by the additional provision of Rs. 38 crores for debt servicing, Rs. 39 crores for grants-in-aid to States and Union Territories, Rs. 9 crores for Administrative Services, particularly under Police and Rs. 20 crores for Social and Developmental Services.

26. The revenue next year is expected to increase by Rs. 125 crores. Here again, if PL 480 grants, which are of a self-balancing nature are left out, the actual increase would be greater. As usual, the principal heads of revenue account for most of the increase; Rs. 70 crores under Income and Corporation Tax, Rs. 54 crores under Union Excise Duties and Rs. 20 crores under Customs. In

addition, interest receipts from State Governments and public sector enterprises and surplus profits of the Reserve Bank will show an improvement of Rs. 39 crores.

27. The provision for capital outlay, including all loans except those to the State Governments and Union Territories, is estimated at Rs. 1,114 crores, representing an increase of Rs. 104 crores over the current year. This is accounted for mainly by larger provision of Rs. 24 crores for roads, Rs. 23 crores for food purchases, Rs. 15 crores for Atomic Energy, Rs. 12 crores for Defence and Rs. 16 crores for the Industrial Development Bank. Loans to State Governments and Union Territories are estimated at Rs. 712 crores, practically at the level of the current year. Loans for Plan assistance, however, will be Rs. 28 crores more, and ways and means loans correspondingly less.

28. The total Plan outlay of the Central and the States next year will be Rs. 2,225 crores, Rs. 241 crores more than the current year's budgeted Plan outlay of Rs. 1,984 crores. The State Plans will account for an outlay of Rs. 1,027 crores and the Central plan for Rs. 1,198 crores. Of the total States' outlay, Rs. 650 crores will be financed by Central assistance and Rs. 377 crores from the resources of the States themselves. The Centre's Plan, it may be noted, will be financed partly by Rs. 160 crores of contribution from the internal resources of Railways, Posts and Telegraphs Department, Hindustan Steel and other public sector enterprises. To this extent, therefore, a provision in the estimates of the Central Government is not necessary. For the balance of Rs. 1,688 crores, inclusive of Rs. 300 crores on revenue account and assistance to States, provision has been made in the Budget. Honourable Members will be glad to note that the contribution of Rs. 160 crores from the Railways, Posts and Telegraphs and public sector enterprises will be Rs. 45 crores higher than in the current year. With more public sector enterprises coming into production and beginning to yield surpluses, they should be able to contribute increasingly to the growth of the economy without putting an additional strain on the budget.

29. I have referred earlier to the need for keeping public borrowing within the limits set by a realistic expectation of the flow of genuine savings. In keeping with this principle, I have provided for public borrowing at Rs. 270 crores next year as against Rs. 293 crores in the current year. For the same reason, receipts from small savings have been assumed at the level of the current year, namely Rs. 135 crores. Receipts from foreign loans, will however be higher and are estimated at Rs. 669 crores.

30. To sum up the overall position for next year, there will be a surplus of revenue account of Rs. 237 crores at existing rates of taxation. The total disbursement on capital account of Rs. 2094 crores, inclusive of debt repayment of Rs. 267 crores, will be met, apart from the revenue surplus, by internal and external borrowings of Rs. 939 crores, collections under small savings of Rs. 13 crores, repayment of loans of Rs. 334 crores, investment of PL 480 funds of Rs. 191 crores, annuity deposits of Rs. 65 crores, and receipts under miscellaneous debt and deposit heads of Rs. 203 crores. In the aggregate, Honourable Members would be happy to know that for the first time in many years, the Budget for next year, at existing rates of taxation, is expected to show a small overall surplus of Rs. 16 crores.

31. Honourable Members might well ask why, after having announced a small surplus for the next year, I should not let the Budget well alone and resume my seat. It is however, necessary particularly on the eve of the Fourth Plan, to take a good look at our tax structure as a whole and to make adjustments or changes to give desirable effects. And it is this that I have sought to do with the proposals I am about to make.

INDIRECT TAXATION

32. Indirect taxation has two essential objectives: to raise revenues for the State and to serve as an instrument of price policy. Those indirect taxes which are designed primarily to raise revenue have to be adjusted not only in the light of revenue needs but also in the light of their impact on the budgets of individual citizens. I feel that in our present circumstances where high prices have put a strain on a section of our people a measure of relief is called for in those areas where the supply position is such that one may reasonably expect the relief to be passed on to the consumer. Clearly given the needs of the State, relief in indirect taxation cannot be extensive. Nor can indirect taxes be reduced in those areas where restraint on consumption is essential from the point of view of economy in imports or releasing larger supplies for exports.

33. In a growing economy with shortages at various levels, there is also a tendency for the price structure to be distorted. It is common knowledge that excessive profits are being made in the sale of products based on scarce materials whether imported or indigenous, and I propose to make selective increases in both import and excise duties to mop up these surplus profits. We have today arrangements for the distribution of scarce materials among priority users. We propose to strengthen these arrangements. It has to be recognised at the same time that control over distribution cannot always be carried to the point where the requirements of all end-users are met through a central agency. Nor is there any reason to eschew the price mechanism to the extent that it can be used to supplement distribution arrangements. What I have essentially sought to do, therefore, is to increase indirect taxation in those areas where it might correct existing distortions in the price structure and mop up some surplus profits and to use the additional revenue from these measures for providing relief to the consumer to the extent possible.

34. My proposals for concessions in regard to indirect taxation relate to excise duties only. I propose to remove the excise duty on footwear, cycle parts, cycle tyres and tubes, printing and writing paper used in the publication of registered dailies including their weekly issues. The effective rates of fabric duty on price-controlled varieties of grey as well as processed coarse and medium cotton cloth are proposed to be reduced by 50 per cent duty on vegetable product by about 50 per cent and on cheaper type of printing and writing paper and certain other qualities of typing and manifold paper by 30 per cent. I also propose on other grounds to reduce the duty on rayon yarn of coarser and industrial deniers, on cellulosic staple fibre and, marginally, on staple fibre yarn. Duties on a few other items such as silk fabrics, gramophones, cigars and silver are also proposed to be removed on grounds of insignificant revenue. These reductions will mean a loss of revenue of Rs. 295 crores in 1965-66.

35. I have made these reductions in duty on articles of common consumption as I expect them to be passed on to the consumer. If this expectation is not realised, it will become necessary to re-impose the duties in the course of the year. That is why the proposed reductions are being made not by reducing the statutory rates of duty but by issuing notifications under powers already vesting in Government.

36. In selecting the items for concessions in excise duty, I have given careful consideration to the reduction of duty on kerosene. I have, however, come to the conclusion that we cannot afford to give relief in duty on kerosene which is an important item of import. Quite apart from this, even at present the duty on kerosene is low enough to encourage its use by lorries and for other non-domestic purposes and there is little to be gained by encouraging further diversion of kerosene to those users.

37. I am also taking the opportunity of making certain technical adjustments in excise duties mainly in respect of cigarettes and tyres. On the present pattern of production, these modifications will increase revenue by Rs. 40 lakhs in the case of cigarettes and Rs. 35 lakhs in the case of tyres. I am sure, it will be possible for the industries concerned to absorb these small technical increases without any overall effect on prices. I have proposed a few other minor changes in the description of goods subject to duty and in the quantum of exemptions. These changes have no significant revenue implications.

38. The profit margins on the distribution of a number of scarce materials and on the sale of their products are high and I intend to mop up a part of the present margin of profits on these items by increases in excise duties. I propose to raise the excise duty on copper and copper alloys in crude form from Rs. 300 to Rs. 1000 per tonne and on circle and sheets etc., from Rs. 500 to Rs. 1500 per tonne. I propose to raise the duty on steel ingots, plates and rails and sleeper bars by Rs. 10 per tonne, on semi-finished products and bars, rods and structurals by Rs. 15 per tonne, on black sheets and hoops by Rs. 40 per tonne, on skelp by Rs. 50 per tonne, on strips by Rs. 90 per tonne and on galvanised plates and sheets by Rs. 100 per tonne. It is also proposed to raise the effective duty on tin plates and tinned sheets from Rs. 165 to Rs. 225 per tonne. The increase of duty on this group will yield an additional revenue of Rs. 15.75 crores.

39. I also propose to further simplify the existing scheme of compounded levy prescribed for the smaller powerloom units producing cotton fabrics. The total exemption now enjoyed by a large number of unit having less than five looms each is being replaced by a small compounded levy of Rs. 25 per annum per loom. The anti-fragmentation provision is also being rephrased.

40 The net loss of revenue as a result of all the changes in excise duties will be Rs 13 crores in 1965-66

41 The revenue from Union Excise Duties has increased steadily from Rs 14 crores in 1955-56 to about Rs 773 crores in 1964-65. It is a matter of some satisfaction that, for the first time in many years, we are able to give a measure of relief to the consumer without any significant sacrifice of revenue in the aggregate

42 Ten days back, I had announced the imposition of a regulatory Customs Duty at 10 per cent of the value of imported goods. This duty must continue in the present circumstances. In addition, it is necessary to increase the present rates of duty in some cases where there is a very large gap between the landed prices and the current market prices. I propose, therefore, to increase the import duty on stainless steel plates and sheets from 30 per cent to 100 per cent *ad valorem* and the duty on steel in plates from Rs 100 per tonne plus 5 per cent to Rs 325 per tonne, continuing the present preference of Rs 20 per tonne where it is applicable. It is also proposed to raise the duty on non-cellulosic art silk yarn and thread from Rs 75 per kilogram or 55 per cent whichever is higher to Rs 1025 per kilogram or 75 per cent whichever is higher. I propose to raise the duty on paints, colours and painters' materials not otherwise specified from 60 per cent to 75 per cent, on sodium hydrosulphite from 40 per cent to 100 per cent, on essential oils and perfumery not otherwise specified from 75 per cent to 100 per cent and on paper not otherwise specified but excluding newsprint and printing and writing paper from 50 per cent to 75 per cent. I also propose to increase the statutory import duty on raw cotton to 50 paise per kilogram in order to be able to increase the effective duty in the course of the year, if this becomes necessary. The increases in import duties along with the surcharge on them will yield a revenue of Rs 6.5 crores in 1965-66. In addition, there will be increase in revenue of Rs 8 crores as a result of the countervailing duty on steel tin plates, iron and steel products and copper. The total additional revenue from Customs will be Rs 14.5 crores.

43 The changes in indirect taxes will have immediate effect under the Provisional Collection of Taxes Act. The net effect including Customs and Excise, will be a small increase in revenue of Rs 1.5 crores in 1965-66.

Export Promotion

44 Honourable Members are aware that we have at present a number of provisions for giving fiscal relief for the promotion of exports. Relief from the incidence of Customs and Excise duties is being given by way of drawbacks. In view of the difficulties experienced by nascent export industries in a growing economy such as ours which is afflicted by shortages at various levels leading to higher cost of production we also give a measure of relief to these industries in regard to railway freights and taxation of profits.

45 While these measures to counteract the disabilities of our export industries have had a degree of success in promoting higher exports, there are still other imposts on raw materials and components that go into the end-product that is exported which makes it necessary to provide some more assistance to export industries on a discriminating basis. For one thing, there are a variety of taxes levied in India today such as the sales tax and octroi in respect of which relief from taxation on exports is not available at present. It is difficult to refund the fractional parts of Import Duties and Excise Duties on raw materials components and intermediate products which enter into the production of export commodities. In general, it is necessary to mitigate the disadvantages of new export industries which have yet to achieve their full competitive position in the world markets. I propose therefore, to take powers to issue tax credit certificates to exporters up to 15 per cent of the value of such exports. The exact quantum of assistance will vary from commodity to commodity and will be determined after a careful examination. The tax credit certificates could be used for payment of taxes or refunded in cash to the extent that their value exceeds tax liability.

46 Honourable Members are aware that the case for protecting the infant industries of developing countries from competition from abroad by levying protective import duties has been recognised by expert opinion as well as by international agencies for a long time. The case for subsidising nascent exports from developing countries is equally strong and is indeed based on the same considerations. This point of view is already gaining acceptance among economic

experts as well as among international institutions. I think it is only appropriate, therefore, that we should aim ourselves with powers to give direct financial assistance related to export earnings so that our export promotion efforts could become more effective as well as efficient.

CORPORATE TAXATION

47. Honourable Members are aware that the structure of our corporate taxation has undergone many changes during the past two years. These were necessitated primarily by the paramount need of raising resources. In my last Budget I had introduced several changes to reduce the severity of our corporate taxation. I am well aware that the feeling still persists that corporate taxation in India is high and that some of its features inhibit the progress of the corporate sector. I have carefully examined the incidence of the different taxes which are now on the statute book and I have come to the conclusion that there is need for some modification of the present structure of corporate taxation without altering its essential features which are sound. The dividend tax, for example, has come in for a great deal of criticism. Experience so far has shown that it has not materially affected the distribution pattern of dividends. I cannot help feeling, however, that in the present context, when we have to do everything possible to combat inflationary pressures in the economy and to generate sufficient resources for investment in the corporate sector, there is continuing need for a degree of restraint on dividend distribution. Similarly, we have not yet had time enough to assess the full effects of the surtax and there is, therefore, little reason for making any material change in this particular aspect of corporate taxation also. However, I have decided to make a number of changes in the general scheme of corporate taxes which, I hope, will meet at least a part of the difficulties of the corporate sector.

48. Industries producing articles mentioned in Part IV of the First Schedule to the Finance Act, 1964, are entitled to certain tax benefits. I propose to enlarge that list by the addition of lime stone, flame and drip proof motors, malleable iron and steel castings, calcium ammonium nitrate and ships.

49. I had announced last year that Section 104 companies wholly or mainly engaged in the manufacture or processing of goods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power whose whole income did not exceed Rs. 5 lakhs will be liable to tax at 50 per cent on the first Rs. 2 lakhs of income. I propose now to enlarge this concession. All such companies—except foreign companies—will under my proposal be liable to tax at 50 per cent on the first Rs. 10 lakhs of their income irrespective of the total size of their income. Under Section 104, for certain types of companies, the penalty rate of taxation for non-distribution of profits at present is 37 per cent. I propose to reduce this rate to 25 per cent for companies other than trading companies. In the case of manufacturing companies, we have given certain concessions to enable them to build up adequate reserves. For non trading companies, e.g., companies part of whose business is in the manufacturing field, companies providing various services and companies engaged in constructional activities, I propose to provide that the higher statutory percentage of 90 per cent for compulsory distribution of profits will be attracted only if the accumulated profits and reserves exceed twice the amount of their paid up capital and loan capital, or the value of their fixed assets. At present, where in a public company 51 per cent or more of the shares are held by another company in which the public are substantially interested or by a 100 per cent subsidiary of such a company, the first mentioned company does not qualify for being regarded as a company in which the public are substantially interested. It is proposed to change this position and to treat such a company as one in which the public are substantially interested.

50. Overcrowding has become a serious problem in many of our major cities. Some incentive is, therefore, required to induce big factories to shift from such cities. I propose, therefore, in the case of public companies to refund the tax on any capital gains made on the sale of land and buildings in these cities to the extent that the capital gains are re-invested with prior approval of Government in land and buildings including housing for the employees in a new area.

51. I had stated last year that I propose to revise the rate of development rebate under Section 33 of the Income Tax Act. Honourable Members will recall that the general rate of development rebate now is 20 per cent. It has been suggested that the development rebate should be applied in a selective manner and we have already sought to do so to some extent in the case of coal mining machinery and for ships. I propose now to reduce the standard rate of development rebate to 15 per cent except in the case of industries included in a new Fifth Schedule to the Income Tax Act. Industries included in this Schedule will be entitled to claim a development rebate of 25 per cent. The rebate for coal mining machinery and for

ships will continue at the rate of 35 per cent and 40 per cent respectively. The undertakings for which the development rebate is now being reduced will, however, continue to enjoy the existing benefit of 20 per cent up to 31st March 1967.

52. Often it is said that the total incidence of income-tax and surtax on companies reaches very high levels having the effect of inhibiting investment. I do not think that it is so, but to allay any misgivings on this score, I propose to provide a ceiling limit to the income-tax excluding the tax relating to bonus issues, but including the tax charged with reference to distribution of equity dividends, and surtax at 70 per cent of the total income of companies. Any excess of the aggregate tax liability in respect of these taxes over this limit will be allowed as a deduction from the surtax otherwise chargeable from the company. This provision will apply to Indian companies and any other company declaring its dividends within India in which the public are substantially interested.

53. The various changes in taxation affecting the corporate sector that I have outlined should go some way in meeting the genuine difficulties of this sector. I also propose to take some additional powers to stimulate production and to provide resources for the expansion of industry. Given the needs of the State, I cannot do so by giving up existing sources of revenue. A part of the improvement in revenues, however, could well be utilized for meeting the requirements of industrial expansion and for providing a stimulus to greater production from existing investments. I propose, therefore, to take powers to provide that tax credit certificates to the extent of 25 per cent of the Central Excise Duty paid by any manufacturing unit on production in addition to its production in the base year may be issued to the unit. Similarly, I propose to take powers to provide for issuing tax credit certificates for 20 per cent of the additional Corporation Tax including surtax paid by any manufacturing company over the corresponding tax paid during the base year. This would be further subject to the limit of 10 per cent of the overall tax for the year concerned. These certificates are meant to be used for purposes relevant to the expansion of the industry namely redemption of debentures or repayment of loan from approved institutions.

54. The Government had recently set up a Tea Finance Committee and that Committee had made certain recommendations for relief in direct tax for tea companies. I propose to accept these recommendations in a modified form and the necessary provisions have been included in the Finance Bill.

55. I also propose to allow in the case of companies a deduction for expenditure incurred by them for payment towards family planning amongst their employees. Where such expenditure is of a capital nature, it will be allowed as a deduction over a period of five years.

PERSONAL TAXATION

56. I now come to my proposals for personal taxation. Honourable Members would recall that earlier in my speech I had referred to the need for curbing excessive investment in urban property which has been rising rapidly in value due to a variety of reasons. Without such a curb, investment in more productive directions cannot be encouraged. There has also been a demand that there should be some ceiling on vast accumulations of urban property. I have considered this problem from various angles and have come to the conclusion that the best way of dealing with it through a fiscal measure is by way of an additional wealth tax on such properties. The tax will apply to urban property in towns with a population of one lakh or more. In view of differences in urban property values in towns of different sizes, I have decided to provide for different exemption limits according as the population of the town is between 1 lakh and 4 lakhs, 4 lakhs and 8 lakhs, 8 lakhs and 16 lakhs and over 16 lakhs. The exemption would vary from Rs. 2 lakhs in the smallest of these ranges to Rs. 5 lakhs in the highest of these ranges. Honourable Members will see that the classification of towns that I have adopted for this purpose is the same as is already available for purposes of granting compensatory and other allowances to Central Government employees. Urban properties in excess of these exemption limits will, under my proposal, bear an additional wealth tax at progressive rates rising from one per cent to four per cent on successive slabs of the total market value of such property. It is not possible for me now to estimate precisely the revenue from this source, but as at present I would put down the additional revenue expected at Rs. 15 crores in 1965-66. I would like to emphasise, however, that the purpose of this levy is as much to raise revenue as also to achieve wider social purposes. It may be that as a result of this measure, property owners may transfer properties to corporate bodies which are not now liable to the wealth tax or property owning companies may come up. If this tendency develops, Government will deal with it at the appropriate time.

57. I propose now to restore the exemption from wealth tax for five years for equity investment in new industrial companies. This concession will apply in respect of companies issuing capital for the first time after the 28th February 1965. The companies issuing bonus shares pay a tax of 12 1/2 per cent on the face value of these shares. It stands to reason that if a person pays capital gains tax on bonus shares issued to him some part of the tax paid by the company on the same issue should go to mitigate his liability for capital gains tax. I propose, therefore, to allow a rebate of 10 per cent of the face value of bonus shares from the capital gains tax on such shares but limited to the amount of such tax.

58. In the region of personal taxation of incomes, the first need is for simplification of the tax structure. For one thing, the distinction between income-tax and super-tax is something of an anachronism and the manner in which we allow for various deductions as at present is also not conducive to either simplicity or comprehension of net incidence. I have endeavoured to simplify the whole tax structure by integrating super-tax with income-tax and in other ways. This simplification will cost something to exchequer for a little while. But it will improve tax administration and help to modify the attitude of the ordinary citizen towards his tax liability.

59. Basically, I wish to provide for a system in which the present free allowance for purposes of income-tax will be discontinued, thus eliminating *inter alia* the element of acute discrimination against unmarried women and bachelors. Incomes in future will be chargeable to tax, subject to relief on account of personal allowance for every individual of Rs. 2000 with an additional allowance of Rs. 1500 for a married individual and Rs. 400 for each dependent child up to a maximum of two children. For a married individual with two dependent children no tax will thus be payable up to an income of Rs. 4300 as against Rs. 4000 as at present. The relief by way of personal allowances will, at the new rate, amount to the same absolute sum of Rs. 215 as a maximum for all assesseees. This simplification will entail a loss of revenue of Rs. 3.64 crores.

60. Another change in the direction of simplification that I wish to make relates to deductions in respect of contributions to provident fund, insurance premiums and Cumulative Time Deposit Scheme. Apart from raising the money limit for concession relating to these items from Rs. 10,000 to Rs. 12,500 for individuals, it is proposed to give the concession by a straight deduction from income of 50 per cent of the amount contributed to the items eligible for the relief. This measure, I am sure, will facilitate the calculation of tax liability by each individual. I am also introducing a new provision for exempting from tax income up to Rs. 2,400 on account of institutional care of handicapped dependents. In the case of non-institutional care the limit will be Rs. 600. Honourable Members would agree with me that a measure of relief in this respect is justified on social grounds.

61. While streamlining the tax structure, and replacing the present taxes by a revised and unified schedule, I have lowered taxes at all levels of personal incomes. In the new schedule, the highest marginal rate of taxation on earned incomes which will be reached at over Rs. 70,000 will be 65 per cent. At the same time, the surcharge on earned income has also been regarded at 5 per cent for incomes between Rs. 1 and Rs. 2 lakhs, 10 per cent for incomes between Rs. 2 and 3 lakhs and 15 per cent for incomes above Rs. 3 lakhs. In our scheme of taxation, we have come to regard an income of Rs. 15,000 as the dividing line for various purposes. The Annuity Deposit Scheme, for example, does not apply to incomes upto Rs. 15,000. I have also decided that the same limit should be considered as the free limit for purposes of the unearned income-tax surcharge. The present limit for this purpose is proposed, therefore, to be raised from Rs. 10,000 to Rs. 15,000. With the base for unearned income-tax surcharge being lowered by this measure as well as by the reduction in tax rates in general, there is a case for increasing the surcharge on unearned incomes. Accordingly, I propose to levy a surcharge on the tax at the rate of 20 per cent on unearned incomes between Rs. 15,000 and Rs. 50,000 and at the rate of 25 per cent on such incomes above Rs. 50,000.

62. The Finance Bill looks very bulky as it contains a number of amendments to the Income Tax Act, 1961. This has in the main become necessary in order to give effect to this scheme of simplification of the tax structure. These amendments are, however, of a permanent nature and will not have to be repeated in future Finance Bills.

63. As I have just said the changes proposed will mean a reduction in tax at all levels of personal income. The highest marginal rate on unearned income will go down from 88.125 per cent to 81.25 per cent and that on earned income from

of income above Rs. 3 lakhs of earned income and above Rs. 70,000 of unearned income. For a married individual with two dependent children, the tax on earned income of Rs. 5,000 will go down from Rs. 60 to Rs. 35, at Rs. 10,000 from Rs. 685 to Rs. 535, at Rs. 20,000 from Rs. 2,360 to Rs. 2,085, at Rs. 40,000 from Rs. 10,340 to Rs. 9,285, at Rs. 70,000 from Rs. 28,590 to Rs. 23,585 and at Rs. 1 lakh from Rs. 44,615 to Rs. 39,160. This has been worked out after taking into account tax benefit on the relative Annuity Deposit. Despite these reductions, our tax rates will still be higher than in countries like the United Kingdom and the United States of America at corresponding levels of income. I make, however, no apology for not reducing personal income taxation in India to the levels prevailing in other countries. For one thing, the same level of income in India and United States of America does not imply the same level of absolute well being. Much less does it imply the same relative position in society as a whole. For a country like India, an income of Rs. 1 or Rs. 2 lakhs represents economic power which is much greater than that enjoyed by people of the same income in more fortunate lands.

64. The loss of revenue as a result of the reduction in tax rates and the changes in surcharges will be of the order of Rs. 20.69 crores in a full year. During 1965-66, there will be an additional loss of Rs. 15 crores on all types of direct taxation in respect of advance collection of taxes. I have, however, every hope that apart from giving a measure of relief to people in the lower and middle income groups the changes I have made will stimulate a greater flow of personal savings and reduce the scope and incentive for tax evasion.

65. Apart from the major changes I have described earlier, I propose to make some other changes in the income-tax provisions. I had announced on the 24th December, 1964 my intention of giving tax credit certificates to individual investors in equity issues of new industrial undertakings, of exempting interest income from funds brought to India and invested in banks in non-resident accounts and exemption of interest on Government securities from the unearned income surcharge. Provision has been made in the Finance Bill to give effect to these changes. It is also proposed to extend the rebate on donations to amounts given for renovation of places of public worship approved in this behalf and also to exempt such gifts from gift tax. The annuity received in respect of the Annuity Deposit Scheme is proposed to be treated as earned income.

66. The present tax concession in favour of foreign technicians whose contracts have been approved by Government is for a period of three years with a grace period of two years where the employer pays the tax. For certain industries and sophisticated processes the services of such technicians have to be retained for a longer period. It is, therefore, proposed that the second period of two years can be extended by a further period of three years with the approval of Government. During the extended period also the tax may be paid by the employer without attracting tax on tax.

67. Representations have been received from professional persons like Chartered Accountants, Architects and Solicitors for tax relief to enable them to make some provision for a superannuation scheme. Recognising the need for this, I propose to give tax relief to partners of firms engaged in the profession of Chartered Accountants, Architects, Solicitors and Lawyers on amounts spent for the purchase of life annuities, commencing at an advanced age, under an approved annuity scheme or sums contributed by them to an approved fund for providing retirement benefits. This relief will be in the form of a straight deduction of such payments from their total income subject to a limit of 10 per cent of the total income or Rs. 5,000 whichever is lower.

68. In order to provide a disincentive for repatriation of funds by foreign investors who sell out their interest in industrial holdings, it is proposed that when such persons reinvest the sale proceeds in approved industrial securities, rebate of capital gains tax, if any, due on the original investment will be allowed in proportion to the amount reinvested.

69. A change is being introduced in the basis of charging taxes on non-resident assesseees as well as resident assesseees who are not ordinarily resident. In order to remove some of the present complications and reduce the rigour of the tax burden, these assesseees will be charged to tax from the assessment year 1965-66 on their income assessable in India at the rates applicable to residents but without deduction of personal allowances for non-residents. The concept of world income is being dropped in their case. The loss of revenue in this case is not material.

70. So far as Estate Duty and Gift-tax are concerned, I propose to enlarge some of the existing concessions and also to amend certain provisions where I find that their interpretation has been causing undue hardship to assesseees. For example, when a person gifts any property during his life time, the property will be liable

for inclusion in the estate on his death under certain circumstances, namely, if he dies within two years after making the gift or if he has possession or enjoyment of the property or any benefit out of it during the two years immediately preceding his death. This requires to be remedied in the light of our present rates of Gift Tax and Estate Duty. I, therefore, propose to reduce the period of two years to one year and further to provide that where Gift Tax has been paid at the enhanced rates of Gift Tax in force from 1964-65 on any gift of property to the wife, son or other close relative, there will be a total exclusion of such property from the estate of the donor if he dies after five years from the date of gift. I also propose to make a provision that if the donor stays in a house which he has gifted to his wife, son or other close relative and there is no right of residence or any benefit reserved to him under the deed of gift, or under any collateral disposition, the property will not be included in the estate if the donor dies after one year from the date of gift. Again, when a pension is given to the family of a deceased employee by Government or by some other body or out of a superannuation fund created by an employer and approved under the Income-tax Act or out of a similar fund maintained by any of the international agencies, the capitalised value of the pension attracts Estate Duty. It is considered necessary to rectify the hardship arising in such cases by exempting such pension from Estate Duty. The loss of revenue as a result of these measures will be nominal. Further, I propose to make a provision for the allowance of stamp duty paid on an instrument of gift as a deduction from the Gift Tax subject to certain limits and conditions.

71. I now come to my proposals in regard to unaccounted incomes and wealth which, as I have already mentioned, are a source of considerable mischief in the economy. The question of how to mitigate this evil is a baffling and difficult one. We have already taken a number of measures, apart from intensification of searches and the like, to encourage voluntary disclosures. Amounts so disclosed are being exempted from penalty. These measures have had some success in encouraging voluntary disclosures particularly from people who have comparatively small and medium incomes to disclose. Various suggestions have been made from time to time to encourage disclosures on a larger scale and to give an opportunity to those who wish to turn a new leaf to do so without undue harassment. I have every hope that with the reduction in tax rates that I have already proposed, the scope and incentive for tax evasion in future would be reduced. The present time therefore, offers a good opportunity to enable people who have evaded tax in the past to come out and make a clean breast of it. I recognise that it is not at all an easy matter to devise a solution which would at the same time be fair to people who have paid taxes honestly in the past and reasonable enough to encourage voluntary disclosures on an adequate scale on the part of those who wish now to be relieved of their past evasion. I have attempted to devise a solution bearing in mind all the complex economic, social and moral considerations that underlie the phenomenon of unaccounted income and wealth. I can only hope that honest taxpayers will not be aggrieved by what I propose to do and that those who have been misled in the past would find in it reason enough to return to the path of civic responsibility.

72. My proposal in brief is this. Those persons who have undisclosed income to declare can make a declaration with relevant particulars and at the same time deposit in cash at the Reserve Bank of India sixty per cent of the income declared. The remaining 40 per cent of the income so declared can be taken to the assessee's books under intimation to income tax authorities. No further question of assessment in regard to the income so disclosed by this process will arise and the identity of the persons will not be revealed. This offer will be open only for three months from now, till the end of May. In order to induce people to come out quickly, a rebate of 5 per cent of the tax on all incomes declared and tax paid thereon in the month of March will be given. In other words, in such cases the effective tax rate will be 57 per cent. Those who feel that their tax liability in respect of amounts to be disclosed would be less than 57 or 60 per cent would be free to resort to normal disclosure and have the income so disclosed taxed at the appropriate rates by income tax authorities after proper assessment. Appropriate provisions are being made in the Finance Bill to give effect to the scheme. I have just outlined. I need hardly add that we propose to continue with our searches. It is incumbent upon the Government to use all the legal weapons at its command to deal with those who spurn this particular opportunity of making voluntary disclosures.

73. I also propose simultaneously to float once again the Gold Bonds. On the last occasion when we issued such a bond, the response did not come up to our expectations. The new bonds will be issued on exactly the same terms as the old bonds except in one respect. In view of the increase in interest rates since the last issue was made the new bonds will carry interest at 7 per cent per annum.

Those who subscribed to the first series of Gold Bonds and thus co-operated with the Government at a time of national crisis will also be given the benefit of this higher rate of interest for the remaining years of the currency of the bonds held by them. Any of the old bonds submitted to the Reserve Bank and bearing the Bank's Imprimatur will bear interest at the new rate after 1st April, 1965. I would like to add that this concession is not to be taken as one that would be ordinarily extended to all similar cases. I would appeal to everyone who holds gold, either under declaration or otherwise, to subscribe to the new bonds to the maximum possible extent. The New Gold Bond will be in the market for a period of three months, i.e., till the end of May, 1965.

SUMMING UP

74. I may now sum up the total effect of the changes that I have proposed. The overall surplus at existing rates of taxation of Rs. 10 crores will be augmented to the extent of Rs. 1.5 crores as a net result of changes in indirect taxation. The loss in revenue of Rs. 29.5 crores as a result of reduction in excise duties on a number of items of daily consumption will be offset by revenue from technical adjustments in respect of cigarettes and tyres of Rs. 75 lakhs, yield of additional excise on copper, steel products and tin plates etc., of Rs. 15.75 crores, and increase in Customs Duties of Rs. 14.5 crores.

75. Among direct taxes, the loss of revenue on account of the introduction of personal allowances will be Rs. 3.64 crores and on account of adjustments in rates Rs. 20 crores making a total of about Rs. 23.64 crores. Modifications in surcharges on earned and unearned income will involve a loss of revenue of Rs. 69 lakhs. The concessions to Section 104 companies will cost to the exchequer Rs. 2.73 crores. Other miscellaneous concessions amount to Rs. 2.34 crores. In addition, there will be a loss of another Rs. 15 crores in 1965-66 in view of the fact that all the new rates in this year will apply both in respect of income taxable during the year and income on which tax might be paid in advance. The wealth tax on urban property will yield a revenue of Rs. 1.5 crores. Thus, as a result of all the changes in direct taxation, including changes in corporate taxation, the total loss to revenue in 1965-66 will be Rs. 42.90 crores.

76. The estimated income under direct taxation from all sources for the year 1965-66 has been put at Rs. 704.05 crores. Out of this Rs. 42.90 crores will have to be deducted as a loss because of the concessions mentioned earlier. However, because of the perceptible lowering in personal taxation and improvement in tax collection, I shall take a credit of Rs. 30 crores making the total estimate of income from direct taxation from all sources Rs. 691.15 crores. This leaves a deficit of Rs. 12.90 crores in direct taxation as against the budgeted figure. As against this, there is a surplus of Rs. 1.5 crores in indirect taxes. Taking this into account and the effect of the States' share in excise duties, there will be a loss of revenue of Rs. 6.38 crores, which together with the overall surplus at the existing levels of taxation will give a net surplus of Rs. 3.78 crores.

77. I have taken no credit for receipts under the voluntary disclosure scheme. Indeed, it is my hope that the entire loss in respect of direct taxation will be more than made up during the year not only by improvement in tax collection resulting from the changes made, but also because of receipts under the voluntary disclosure scheme. It may, therefore, well be expected that we might end up next year with a larger surplus. It is with this in view that I have not estimated any diminution in the States' share of direct taxes revenue. On the other hand such increases in the States' share of Income Tax revenue as would accrue would in my view more than compensate the reduction in the States' share in the revenue from Excise Duties.

78. It is a matter of some satisfaction to me to be able to present this Budget which holds every promise of being a balanced one—if not a surplus one—taking both the Revenue and Capital accounts together. Honourable Members, I hope, will also find similar satisfaction in the fact that we have been able to present a balanced budget while providing for the needs of the Plan and giving a measure of relief in direct and indirect taxation. In conclusion I would appeal to Honourable Members and to all those affected by our tax system that they should treat the present Budget as an earnest of our desire to put the tax structure in this country on an enduring and rational basis.

SUMMARY OF

STATEMENT A

REVENUE BUDGET

(In lakhs of Rupees)

	Budget 1964-65	Revised 1964-65	Budget 1965-66
RECEIPTS			
Customs	3,36,37	3,85,00	4,05,00
Union Excise Duties	7,69,54	7,73,05	8,27,17
Corporation Tax	2,96,67	3,42,00	3,86,00
Taxes on Income	2,47,28	2,68,00	2,94,00
Estate Duty	7,40	7,00	7,40
Taxes on Wealth	10,20	11,05	12,00
Expenditure Tax	1,55	75	1,55
Gift Tax	3,10	3,10	3,10
Other Heads	21,57	21,93	23,87
Debt Services	2,52,14	2,65,57	2,96,73
Administrative Services	8,98	9,13	9,51
Social and Developmental Services	28,13	30,40	23,57
Multi purpose River Schemes etc	11	12	13
Public Works etc	3,75	3,90	3,94
Transport and Communications	6,81	7,14	6,75
Currency and Mint	53,73	52,11	61,69
Miscellaneous	17,29	21,38	25,47
Contributions and Miscellaneous Adjustments	31,08	32,71	34,81
Extraordinary Items	1,43,31	1,24,62	60,50
Deduct—Share of Income-tax payable to States	—1,07,49	—1,23,77	—1,22,93
Deduct—Share of Estate Duty payable to States	—7,22	—6,78	—7,17
TOTAL	21,24,30	22,28,41	23,53,09
			—6,38*

DISBURSEMENTS

Collection of Taxes, Duties and other Principal			
Revenues	25,34	26,41	28,88
Debt Services	3,81,41	3,17,61	3,56,11
Administrative Services	81,84	82,17	91,36
Social and Developmental Services	1,68,14	1,65,11	1,84,66
Multi-purpose River Schemes etc.	1,84	1,33	1,98
Public Works etc.	20,21	20,66	22,98
Transport and Communications	10,18	10,37	10,62
Currency and Mint	17,33	15,36	16,40
Miscellaneous	98,51	95,17	1,16,27
Contributions and Miscellaneous Adjustments			
Grants to States and Union Territory Governments	2,89,08	2,88,56	3,27,11
States' share of Union Excise Duties	1,40,98	1,27,34	1,40,84
Other Expenditure	4,13	4,32	4,69
Extraordinary Items	1,47,52	1,28,04	65,84
Defence Services (Net)	7,17,80	7,16,81	7,48,74
TOTAL	20,41,31	19,99,26	21,16,48
Deficit (—)	(+) 82,99	(+) 2,29,15	(+) 2,36,61
Surplus (+)			—6,38*

*Effect of Budget proposals

FINAL ESTIMATES

STATEMENT B
CAPITAL BUDGET

	(In lakhs of Rupees)		
	Budget 1964-65	Revised 1964-65	Budget 1965-66
RECEIPTS			
Revenue Surplus	82,99	2,29,15	2,36,16]
Public Debt :—			—6,38*]
Raised in India	3,00,00	2,97,70	2,70,00
Raised abroad	6,96,97	6,53,92	6,68,86
Repayment of Loans and Advances :—			
States and Union Territories	2,38,92	2,31,31	2,73,69
Others	46,03	70,00	60,00
Small Savings (Net)	1,25,00	1,35,00	1,35,00
Provident Funds (Net)	54,29	49,62	54,66
Income Tax Annuity Deposits (Net)	67,00	65,00	65,00
Deposits of P. L. 480 Funds (Net)	84,84	11,00	1,91,00
Railway and P. & T. Funds (Net)	43,12	17,81	48,23
Special Development Fund (Net)	2,97,65	2,75,50	1,43,16
Other Debt, Deposits etc. (Net)	1,25,86	51,69	37,74
TOTAL	19,92,99	20,87,70	21,83,95]
			—6,38*]
DISBURSEMENTS			
Revenue Deficit			
Capital Expenditure :—			
Civil	3,86,01	3,42,96	3,59,73
Defense	1,35,10	1,17,95	1,30,05
Railways	2,53,00	2,51,92	2,40,00
P. & C.	20,59	26,59	32,83
Repayment of Debt :—			
Raised in India	1,92,00	1,91,54	1,70,00
Raised abroad	67,26	85,11	97,29
Loans and Advances :—			
States and Union Territories	6,21,71	7,07,92	7,12,07
Others	2,38,22	2,71,01	3,51,82
TOTAL	19,14,89	19,95,00	20,93,79
A11—National transfer of loan assistance to the special Development Fund	1,74,78	1,73,00	80,00
Total Disbursements	20,89,67	21,68,00	21,73,79
Overall Deficit (—)	—96,68	—80,30	+10,16]
Surplus (+)			—6,38*]
To be met by :			
(i) Expansion (+)/contraction (—) of Treasury Bills	+96,00	+72,00	—10,00]
			+7,00*]
(ii) Drawing down of Cash Balance	68	8,30	—16]
			—62*]
Total	96,68	80,30	—10,16]
			+6,38*]

*Effect of Budget proposals.

